RNI Reference No. 1328500

16-31 दिसम्बर, 2018

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 11/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

कौशल विकास से ही कुशल होगा हिमाचल : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

हिमाचल के युवाओं का हुनर तराशेगा आईआईआरडी

अलग – अलग ट्रेड्स में युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण

बाहरी राज्यों में तीन हजार से अधिक अभ्यर्थियों को किया जा चुका है प्रशिक्षित

द रीव टाइम्स (अंजना ठाकुर)

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कनार्टक में युवाओं के कौशल को विकास देने के बाद अब आईआईआरडी हिमाचल में भी युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें भविष्य की बेहतर नींव रखने और हुनर को तराशने में सहयोग करेगा। खास बात यह कि हाल ही में आईआईआरडी को एनएसडीसी यानि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से साझेदार के तौर पर प्रशिक्षण के लिए अधिकृत कर दिया गया है। आईआईआरडी हिमाचल की इकलौती ऐसी संस्था है जो देश के 21 राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। बात अगर कौशल विकास की करें तो इसमें भी आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। झारखंड में जनजातिय महिलाओं के कौशल संवर्द्धन के लिए प्रोजेक्ट रूपातंरण के लिए उत्कृष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित हो चुकी आईआईआरडी यूपी, उत्तराखंड में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न केंद्रों पर अभी तक तीन हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य निर्माण में सहयोग कर चुकी है। हिमाचल के युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि आईआईआरडी अब हिमाचल में भी कौशल विकास केंद्र खोलकर प्रदेश के युवाओं का हुनर तराशने के लिए तैयार है। इसकी शुरूआत जिला शिमला से की जा रही है।

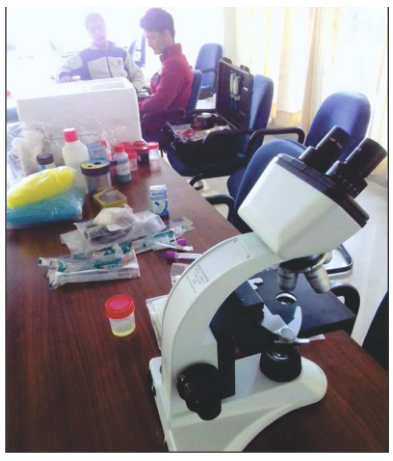

दरअसल, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को जिला में पांच केंद्र चलाने के लिए अधिकृत किया गया। हर केन्द्र पर 60–60 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अभ्यार्थियों को आईटी और हैल्थ सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण में आईआईआरडी इसलिए भी अन्य के मुकाबले बेहतर और विश्वसनीय है क्योंकि संस्था

कौशल विकास के पथ पर आईआईआरडी के लक्ष्य

- आईआईआरडी निजी क्षेत्र में कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की ऐसी संभावनओं को तलाश रहा है जिसमें उद्यमियों सहित कारोबार के ऐसे विचार पैदा हों जहां हम युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सम्मानित वेतन के साथ जोड़ सकें। सेवाक्षेत्र ऐसी कई संभावनाओं से भरा पड़ा है।कौशल विकास विश्वविद्यालय ऐसा हो जहां कारोबारी तैयार किए जा सकें, कारोबार के विकल्प तैयार किए जा सके और कारोबार के लिए आवयश्क मानव संसाधन तैयार किए जा सके।

प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। दूसरे राज्यों में विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षित युवाओं का आंकड़ा इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कौशल विकास में आईआईआरडी के पास दूसरों के मुकाबले लंबा और बेहतरीन अनुभव है। आंकड़ों पर गौर करे तो उत्तर प्रदेश के जिला चंदोली में ही विगत वर्षों में विभिन्न केंद्रों पर एक हजार से भी अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा चुका है। चंदोली केंद्र में वित्त वर्ष 2014–15 में 273, 2015–2016 में 393, 2016–17 में 193, 2017–18 में 178 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह मैथला केंद्र

में वित्त वर्ष 2017–18 में 107 और सैयदराजा में भी इसी दौरान 107 को प्रशिक्षित किया गया जबकि देरहावाल में वित्त वर्ष 2018–19 में 54 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के ही कासगंज जिले में भी कासगंज–1 केंद्र पर वित्त वर्ष, 2015–2016 में 54, 2016–17 में 108, 2017–18 में 200 और 2018–19 में 100 स्थान कुल 462 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कांसगंज–2 केंद्र पर वित्त वर्ष 2017–2018 में 216 और 2018–19 में भी 216 यानि कुल 432 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी तरह गोरखपुर, देवरिया, महागंज में भी करीब 900 युवाओं का पंजीकरण विभिन्न केन्द्रों पर किया गया जबकि अन्य केंद्रों पर प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड के पौड़ी और हरिद्वार में भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया पीएमकेवाई के तहत जारी है।

यहां समझे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का महत्व

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। आजीविका गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है। इस योजना से 550 लाख से अधिक ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को जो कुशल होने के लिए तैयार हैं, स्थायी रोजगार प्रदान करने के द्वारा लाभ होगा। इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation @ NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इकाइयां कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं लेकिन उनसे फायदा लेने के लिए जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में NSDC की बड़ी भूमिका है जिससे निजी इकाईयों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 21 भिन्न–भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केन्द्रित करती है जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उसमे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अब आईआईआरडी भी एनएसडीसी के साथ साझेधार के तौर पर काम करने के लिए पूरे देश में अधिकृत है।

जिला गोरखपुर

केंद्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
भोपा बाजार	2017–18	108
तुरा बाजार	2017–18	105
	2018–19	63
मालहन पार	2017–18	27
	2018–19	81

जिला देवरिया

बीआरडी गेट	2016–17	27
	2017–18	108
सिविल लाइन	2017–18	108

जिला महागंज

परतावल	2017–18	27
	2018–19	54
मिथौरा	2018–19	81
महादेवा	2018–19	108
कुल		897

उत्तर प्रदेश जिला कासंगंज

केंद्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
कासंगंज–1	2015–16	54
	2016–17	108
	2017–18	200
	2018–19	100
कुल		462

उत्तर प्रदेश जिला कासंगंज

केंद्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
कासंगंज–2	2017–18	216
	2018–19	216
कुल		432

जिला चंदौली

केंद्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
मैथला	2017–18	107
सैयदराजा	2017–18	107
कुल		214

जिला चंदौली

केंद्र	वित्त वर्ष	पंजीकृत
चंदौली	2014–15	273
	2015–16	393
	2016–17	193
	2017–18	178
कुल		1037

जिला शिमला

सैक्टर	लक्ष्य
आईटी	60
स्वास्थ्य	180
रिटेल	60

मिशन रीव दे रहा है एक सुनहरा अवसर

यदि आप में है जज़्बा समाजसेवा और उद्यमशीलता का तो आपके सपनों को साकार करेगा मिशन रीव

अपने 10 सेवा प्रभागों में विभिन्न पदों के लिए करें आवेदन और पाएँ पद, प्रतिष्ठा और सम्मानजनक रोजगार वो भी अपने गांव, ब्लॉक और ज़िला में।

मिशन रीव अपने 10 सेवा प्रभागों में पंचायत स्तर से राज्य सचिवालय स्तर तक विभिन्न पदों के लिए आवेदन आंमत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए वांछित योग्यताएँ एवं संपूर्ण विवरण इस प्रकार है :

सृजित पद	पदों की संख्या
प्रभागीय प्रमुख/डिविजनल हैड	10
ज़िला कार्यक्रम प्रबन्धक/प्रोग्राम मैनेजर	120
ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी/प्रोग्राम ऑफिसर	780 जिसे आवश्यकतानुसार उचित समय पर बढ़ाया जाएगा
पंचायत सेवा सहायक/सर्विस ऐसोसिएट	10 प्रति पंचायत

राज्य स्तर पर :

- राज्य डिविजन हैड, स्वास्थ्य प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, कृषि प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाईन सेवाऐं
- राज्य डिविजन हैड, उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, सर संपत्ति प्रबंधन प्रभाग
- राज्य डिविजन हैड, मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

ज़िला स्तर पर :

- प्रोग्राम मैनेजर स्वास्थ्य प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर कृषि प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाईन सेवाऐं
- प्रोग्राम मैनेजर उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर संपत्ति प्रबंधन प्रभाग
- प्रोग्राम मैनेजर मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

ब्लॉक स्तर पर :

- प्रोग्राम ऑफिसर स्वास्थ्य प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर कृषि प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाईन सेवाऐं
- प्रोग्राम ऑफिसर उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर संपत्ति प्रबंधन प्रभाग
- प्रोग्राम ऑफिसर मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

पंचायत स्तर पर :

- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, स्वास्थ्य प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, कृषि प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, यूटिलिटि, लाईसेंस एवं अन्य ऑनलाईन सेवाऐं
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, बैंकिंग, फाइनांस एवं इंश्योरेंस प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, संपत्ति प्रबंधन प्रभाग
- पंचायत सर्विस ऐसोसिएट, मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन प्रभाग

प्रार्थी के चयनोपरांत 10 सेवा प्रभागों में विभिन्न मिशन रीव सेवाओं को आमजन तक पहुंचाना, प्रबन्धन करना, तथा ग्रामीण स्तर पर उसका क्रियान्वयन करना होगा। प्रभागों में यहां बताई गई समस्त सेवाओं को पूर्णतः संचालित करने की जिम्मेवारी उस प्रभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी की होगी। बताए गए सेवा कार्यों के अलावा उस प्रभाग से संबन्धित अन्य समस्त कार्य भी शामिल है।

स्वास्थ्य डिविजन

- जनऔषधि केंद्र– लोगों को घर द्वार पर सस्ती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन– लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

कृषि डिविजन

- मृदा परीक्षण लैब– सदस्यों और किसानों के लिए सेवाऐं
- जैविक खाद निर्माण–किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
- बीज और कृषि उपकरण–किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
- फीड सप्लीमेंट– पशुओं में दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
- जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन

- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाऐं उपलब्ध कराना
- ई– स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाऐं

उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन

- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाऐं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरु करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधि सेवाऐं
- संपत्ति प्रबंधन,जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधि सेवाऐं

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर परीक्षण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यस्क आयुवर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई–लर्निग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाऐं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सदुपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाऐं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का क्रय– विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

संपत्ति प्रबंधन डिविजन

- संपत्ति संबंधि देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाऐं
- नक्शा तैयार करवाने और स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग

मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन

- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना
- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर तथा ईमेल पर संपर्क करें

0177– 2640761, 2844073 anand@iirdshimla.org info@iirdshimla.org hr@iirdshimla.org

सोलन ज़िले के अर्की में

गुजराज से आए आईटी के युवाओं को दी मिशन रीव की जानकारी

रीव 2 में ग्रामीण प्रबन्धन को युवाओं ने सराहा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ग्रामीण प्रबन्धन में तकनीकि विकास विषय पर सामाजिक सेवारत इन्केडिबल हिमाचल द्वारा गुजरात के आईटी प्रशिक्षण संस्थान से आए युवाओं को 21 दिन का प्रशिक्षण /ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है । इसके तहत इन युवाओं को विभिन्न विषयों की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है । साथ ही इन युवाओं को हिमाचल की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का आगाज़ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त एवं सहायक संपादक द रीव टाइम्स हेम राज चौहान ने किया । उन्होंने ग्रामीण विकास में तकनीकि पहलुओं को जोड़ते हुए मिशन रीव पर वक्तव्य दिया और कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को दिशा देने के लिए आईटी की भूमिका की ही आवश्यकता है। तकनीक की आवश्यकता ग्रामीण प्रबन्धन में प्रत्येक क्षेत्र में है जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, उद्यमिता आदि। उन्होंने गुजरात से आए सभी युवाओं का स्वागत किया और कहा कि हिमाचल में उन्हें इन 21 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा । प्रदेश के अनेक ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाऐगा तथा गांव में सर्वे करवाकर लोगों की समस्याओं को जाना जाऐगा । मिशन रीव संस्करण 2 पर संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

इससे पूर्व इन्केडिबल हिमाचल के चेयरमैन नीरज गुप्ता ने समस्त युवाओं को स्वागत किया । उन्होंने कहा कि संस्था ने इस प्रयास से एक प्रकार से राज्यों में युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान भी करने का प्रयास किया है ।

हेम राज चौहान ने अपने प्रस्तुतिकरण में युवाओं को गांव में संस्थागत तरीके से

गुजरात से आए युवाओं के लिए 21 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

समस्याओं को सुलझाने पर जोर देते हुए बताया कि समस्याओं को सुलझाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना होता है। इसके लिए व्यवहारिक रुप से कार्ययोजना निर्माण पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्ययोजना निर्माण में ग्रामीणों की सहमति और समस्याओं का प्राथमिकिकरण कैसे होता है, इस पर बताया। युवाओं ने भी एक कार्ययोजना वित्त वर्ष के लिए तैयार की। साथ ही मिशन रीव के दस प्रभागों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मिशन रीव के तकनीकि पहलुओं पर युवाओं ने प्रस्तुतिकरण किया ।

रोहड़ू में मृदा के 100 से अधिक मृदा नमूने सैंपल की जांच

लोगों ने रीव मृदा जांच शिविर में लिया बढ़चढ़ कर भाग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव किसानों को अब अपनी खेती और खेत मृदा जांच के बाद उनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। ज़िला शिमला में रीव मृदा जांच शिविरों में आवश्यक जानकारियों को प्राप्त कर किसान अपने खेतों की मृदा जांच को सैंपल दे रहे हैं। इसी प्रकार ज़िला शिमला के रोहड़ू और आसपास के क्षेत्रों में किसानों के लिए रीव मृदा जांच शिविर आयोजित किए गए तथा उसमें किसानों ने बड़ी तादात में भाग लिया । रीव मृदा जांच टीम ने 100 अधिक किसानों के सैंपल टैस्ट हेतु लिए हैं तथा उनकी रिपोर्ट किसानों को दी जा रही है ।

गौरतलब है कि किसानों से सैंपल लेने के बाद उसे रीव मृदा जांच लैब में तकनिशियन जांच करते हैं तथा उस पर विशेषज्ञ अपनी राय यानि परामर्श से किसानों को लिखित रिपोर्ट में जानकारी देते हैं । अभी हाल ही में जुब्बल आदि क्षेत्रों में भी किसानों के व्यापक पैमाने पर सैंपल लेकर जांच की गई थी । जिसमें किसानों को उनकी मिट्टी के आवश्यक तत्वों की जानकारी और कमियों आदि को किस प्रकार पूरा किया जाना है, बताया गया ।

रोहड़ू में भी किसानों ने अपना उत्साह रीव मृदा जांच शिविर में दिखाया है तथा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं । जांच के बाद किसानों को रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रीव जैविक खाद आदि भी उपलब्ध करवाई जाऐगी ।

क्या कहते हैं अतिरिक्त ज़िला समन्वयक अंकुश नगरैक

रीव मृदा जांच टीम के सदस्य एवं मिशन रीव एडीसी अंकुश नगरैक के अनुसार गांव–गांव में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रीम मृदा जांच टीम किसानों से बात कर शिविरों का आयोजन कर रही है । इन शिविरों में किसानों ने बहुत उत्साह दिखाया है। रोहड़ू और आसपास के क्षेत्रों में 100 अधिक किसानों के खेतों की मृदा जांच की गई है । साथ ही किसानों ने भी रीव मृदा जांच की सराहना की है । घर–द्वार पर ही यह सुविधा किसानों को लाभान्वित कर रही है ।

ज़बरदस्ती सड़क निर्माण से लोग परेशान

कोई नहीं सुन रहा फरियाद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संजौली इंजनघर से नीचे की ओर बिल्कुल सीधे खड़े रास्ते को गुपचुप तरीके से सड़क में बदलने की मुहिम चलाई जा रही है जिससे वहां रास्ते के साथ बने सभी मकान मालिकों को बहुत परेशानी हो गई है। विरोध के बावजूद सड़क को बनाने की जिद्द कहीं न कंही भविष्य के लिए ख़तरा पैदा कर देगी। दरअसल संजौली में इंजनघर के साथ पार्किंग के पास से नीचे की ओर सीधी सीढ़ीयां उतरती है । क्योंकि अब यह एक बड़ी कलौनी बन चुकी है इसलिए मकान भी वहां से काफी नीचे तक बन चुके हैं । शिकायतकर्ताओं के अनुसार, नीचे की ओर जिन्होंने मकान बनाए हैं उनमें कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल उन सीढ़ीयों को सड़क बनाने के लिए करना चाहते हैं तथा जहां तकनीकि और भौगोलिक दृष्टि से सड़क बन ही नहीं सकती, वहां बिल्कुल सीधी खड़ी सड़क बनाकर साथ में बने मकानों एवं लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरे

में डालना चाहते हैं।

सेवानिवृत प्रिसिंपल एवं चेयरमैन आईआईआरडी प्रोफेसर आर के गुप्ता ने कहा कि वो और उनकी पत्नी इस वृद्धावस्था में अपने मकान एवं जगह को बचाने तथा इस सड़क के बनने व भविष्य के लिए ख़तरा होने के कारण काफी परेशान है। इस उम्र में उनसे अब अस्वस्थता के कारण चला भी नहीं जाता है । ऐसे में ये कौन सी और किसकी मिलीभगत है कि हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है । उन्होंने कहा कि उनका मकान 150 साल से भी अधिक पुराना है जिसे नया रुप बाद में दिया गया । यहां आसपास रह रहे लोगों के लिए मकान के साथ रास्ता है । ऐसे में अब उस रास्ते को कुछ लोग सड़क में बदल कर खनन का कार्य आरम्भ कर चुके हैं जिससे हमारे मकान असुरक्षित हो जाऐंगे तथा सड़क भी गाड़ियों के लिए नहीं बन पाऐगी क्योंकि यह सीधी खड़ी होगी । प्रोफेसर आर के गुप्ता ने बताया कि इस बाबत कई बार प्रशासन और नगर निगम को अवगत करवाया गया लेकिन इस पर कोई सटीक समाधान नहीं हो पाया । अब वो परेशान हो चुके हैं और इस समस्या का हल चाहते हैं ।

इस सड़क का जहां से खनन कार्य आरंभ हुआ वहां साथ के मकान ने अदालत से स्टे लिया है बावजूद इसके काम नहीं रुका है । वहां के बाशिंदों ने सड़क को न बनाने की गुहार लगाई है ।

पौधों को खाद देने की विधि

डा. वी.के. शर्मा

पौधों से सही फसल प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उन्हें सही समय पर खाद दी जाए। खाद कैसे दी जाए यह जानना भी बेहद अहम है। ज्यों–ज्यों पेड़ पर विकास और वृद्धि होती है उसकी जड़े मृदा में नीचे की ओर और धरातल के साथ फैलती है। जड़े पानी की तलाश में दूर तक चली जाती हैं। साधारण तौर पर नव रोपित या एक वर्ष के पेड़ की जड़े मृदा में एक फुट तक नीचे और इतनी ही मुख्य जड़ के इर्द–गिर्द फैलती है। इसलिए पेड़ की जड़ों के पास ही खाद डाले। पूरे व्यस्क या 10 साल की आयु से बड़े पेड़ की जड़े मुख्य जड़ से काफी दूर तक चली जाली है। पोषक तत्वों को प्राप्त करने वाली जड़े मुख्य जड़ से एक मीटर दूर तक फैल जाती है। इसलिए व्यस्क पेड़ों में मुख्य तने से 30 सेंटीमीटर दूर तक खाद डाले। पेड़ जैसे–जैसे व्यस्क होता है उसके तौलिये का आकार भी बढ़ जाता है। ऐसे में तौलिए के छोर से 30 सेंटीमीटर अंदर पेड़ के तने की ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 3–4 सेंटीमीटर गहरी नाली बना ले। यह नाली पेड़ के तौलिये के वृत में होगी। इस नाली की मिट्टी एक तरफ कर लें और खाद की निर्धारित मात्रा डालकर उसे वहीं की निकाली हुई मिट्टी में ढक लें। खाद डालने के लिए वहां नमी का होना आवश्यक है। इसलिए खाद डालने के लिए बारिश या बर्फबारी के तुरंत बाद का समय बेहतर है। नमी और जल से उर्वरकों का विघटन आसानी से हो जाता है और खाद पूर्ण रूप से जड़ों तक पहुंच जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सूखे मौसम में खाद न डालें। गोबर की खाद और अन्य प्राकृतिक खादें कुछ दिन मृदा में ढकी रहने पर भी उपलब्ध हो जाती है। सुपर फॉस्फेट की भी यही स्थिति है लेकिन कैन खाद का प्रयोग इस अवस्था में न करें। शुष्क अवस्था में इसकी नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का 11वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। 'द रीव टाइम्स' लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बने साहिल उपमन्यु

दो माह में सैंकड़ो लोगों को घर पर ही दी सेवाएं

टीम रीव, ऊना

मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। काम कैसा भी हो अगर मन में उसे करने की ठान ली जाए तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, इस बात को सच कर दिखाया है ऊना में मिशन रीव प्रतिनिधि साहिल उपमन्यु ने। साहिल ने बतौर पंचायत फेसिलिटेटर 2017 में मिशन रीव ज्वाइन किया। काम के आधार पर साहिल को पीएफ से पद्दोन्नत कर सहायक ब्लॉक संयोजक बनाया गया। साहिल का कहना है कि वह काफी समय से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे लोगों के काम आसानी से हो जाए। जब उन्होंने मिशन रीव ज्वाइन किया तो उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। साहिल की माने तो उन्होंने सैंकड़ो लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद की और तीन माह के भीतर स्वंय भी लाखों की आय मिशन रीव मॉडल के आधार पर प्राप्त की। बीते मार्च–अप्रैल में तो इसी मॉडल के आधार पर साहिल ने दो माह में दो लाख सात हजार की आय प्राप्त की।

रीव मॉडल के तहत इस तरह किया काम

साहिल ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने सदस्यता अभियान के तहत गांव के लोगों को मिशन रीव से जोड़ा और सभी लोगों को मिशन रीव की जानकारी दी। साहिल ने लोगों को बताया कि रीव कैसे दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकता है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब गांव के कुछ लोगों को काम उन्होंने किए तो बहुत से लोगों ने काम कराने में मदद मांगी।

इसके अलावा लाइसेंस बनाने, सरकारी योजनाओं के तहत ट्रैक्टर लेने में मदद करने के लिए भी लोगों ने कहा। दरअसल, गांव के लोगों को इन योजनाओं की न तो पूरी जानकारी थी और न ही दस्तावेज तैयार करने के बारे में कुछ पता था। साहिल ने लोगों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने में मदद की। साहिल ने तीन लोगों को होम लोन दिलाने में मदद की तो वहीं चार लोगों को खादी लोन दिलवाए।

इसके अलावा एक व्यक्ति को डिस्पोजेबल ग्लास प्लांट लगाने में सहयोग दिया तो वहीं सरकारी योजना के तहत गांव के किसानों को ट्रैक्टर दिलाने में भी पूरा सहयोग लिया। साहिल ने करीब 150 लोगों के लाइसेंस बनवाए और 80 से अधिक लोगों के लाइसेंस

मिशन रीव ने आसान की सैंकड़ो लोगों के जीवन की राह

किसी को दिलाया लोन तो किसी ने बनवाए लाईसेंस

ऊना, टीम रीव

मिशन रीव के तहत ऊना के गांवों में लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिशन रीव से गांव के लोगों का जीवन आसान हो गया है। बात लोन लेने की हो, किसी काम को करने के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र लेना हो या बिल जमा कराने जैसे रोजमर्रा के काम हो, सभी मिशन रीव के तहत आसानी से हो जाते हैं। ऊना में कई ऐसे उदाहरण है जब लोगों के पेजिदा काम भी घर बैठे हो गए। जिला की गुगलैहड़ पंचायत में मिशन रीव के तहत लोन प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त किया तो वहीं लोगों ने डेयरी और फुटवेयर जैसे व्यवसाय भी मिशन रीव के सहयोग से स्थापित किए। ऊना के चानन सिंह ने बताया कि वह काफी समय से लोन लेना चाहते थे लेकिन इसके लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि संबंधित दस्तावेजों को जुटाने का न तो उनके पास समय था और न ही यह पूरी तरह पता था कि लोन कहां से कैसे प्राप्त करना है। इसके बाद मिशन रीव प्रतिनिधि साहिल उपमन्यू से बात की। साहिल ने स्वंय पूरी औपचारिकताएं पूरी की और उन्हें खादी लोन मिल गया। इसके लिए न तो उन्हें दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े और न ही अन्य कोई खास परेशानी झेलनी पड़ी। इसके साथ ही चानन सिंह ने मिशन रीव के सहयोग से गाड़ी भी खरीदी। चानन के मुताबिक गाड़ी खरीदने के लिए जो भी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी थी वह सभी मिशन रीव के प्रतिनिधि के तौर पर साहिल ने पूरी करके दी। इसके अलावा मिशन रीव के तहत 200 से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मदद की गई तो कई लोगों को व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान नहीं क्योंकि इसके लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मिशन रीव के तहत अब सब कार्य आसानी से हो जाते हैं।

सोलन–सिरमौर में वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ावा देगा मिशन रीव

जैविक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

टीम रीव सोलन/सिरमौर

जंगली जानवरों और मौसम की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए मिशन रीव जल्द ही वर्टीकल फार्मिंग यानि खड़ी खेती को अपनाने में किसानों की मदद करेगा।

इसमें जहां किसानों को खड़ी खेती के बारे में विस्तार से बताया जाएगा वहीं खेती करने के लिए जरूरी ढांचा तैयार करने और उत्पादित फसल को बाजार तक पहुंचाने में भी किसानों की मदद की जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो खड़ी खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नही होता।इसे कम भूमि वाले खेतिहर किसान को काफी लाभ मिल सकता हैं और खड़ी खेती के माध्यम से किसानो की आय को भी बढ़ाया जा सकता हैं।

खड़ी खेती क्या हैं?

खड़ी खेती या वर्टीकल फार्मिंग में एक बहु–सतही ढाँचा तैयार किया जाता हैं, इस ढाँचे के सबसे निचले हिस्से में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता हैं। टैंक के ऊपरी खानों में पौधों के छोटे–छोटे गमले रखे जाते हैं, पाइप के द्वारा इन गमलों में उचित मात्रा में पानी पहुँचाया जाता हैं जिसमें पोषक तत्व मिले होते हैं जो पौधों को जल्दी बढ़ने में मद्द करते हैं। (एलइडी बल्ब) के द्वारा कृतिम प्रकाश बनाया जाता हैं।

खड़ी खेती के लाभ

बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि भविष्य की एक बहुत बड़ी समस्या होगी. आने वाले समय में खेती योग्य भूमि बहुत कम होगी ऐसे समय में वर्टीकल खेती या खड़ी खेती ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकता हैं। (खड़ी खेती) के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता हैं। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता हैं, जिसके कारण मौसम सम्बन्धी समस्याओं से संरक्षण प्राप्त होता हैं। फ़सल नष्ट होने या खराब होने की संभावना कम होती हैं। परम्परागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता हैं जिससे तरह–तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। खड़ी खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता हैं और इसमें उत्पादित फसल स्वास्थ के लिए लाभदायक होता हैं। खड़ी खेती की वजह से जब कम जमीन में उत्पादन अधिक होगा तो किसानो की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

इस प्रकार की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती हैं। कम वर्षा वाले जगहों के लिए वर्टीकल फार्मिंग एक सही विकल्प हो सकता हैं। खड़ी खेती में मजदूर की आवश्यकता कम होती हैं क्योंकि यह ऑटोमेटेड तकनीकी पर आधारित खेती हैं। यानि इस खेती को बेहद कम मानव संसाधनो के साथ किया जा सकता है। यदि आप कृषि व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो खड़ी खेती आपके लिए एक विकल्प हो सकता हैं। अभी भारत में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और कुछ लोग खड़ी खेती से करोड़ों रूपये कमा चुके हैं।

ऊना में तैयार हो रहा जैविक खाद का भंडार

किसानों को घर पर ही दिया विशेष प्रशिक्षण

टीम रीव, ऊना

प्रदेश के दूसरे राज्यों की तर्ज पर जिला ऊना में भी किसानों को मिशन रीव के तहत खाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला की गुगलैहड़ पंचायत में अनेक किसानों को मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर जैविक खाद बनाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि रासायनिक खाद किस तरह कुछ समय के लिए फसल की पैदावार को बढ़ावा देती है लेकिन मृदा की उपजाऊ शक्ति को कम देती है।

प्रशिक्षण के बाद किसानों ने अपने घर पर ही जैविक खाद बनाना शुरू कर दी है। खाद तैयार होने के बाद मिशन रीव के तहत इन किसानों को खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करावाया जाएगा।

हाल ही में सोलन में भी किसानों ने मिशन रीव के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खाद का भंडार तैयार किया और उस खाद की बिक्री अपने घर से ही करके बिना परेशानी झेले 10 से 15 हजार तक अतिरिक्त आय प्राप्त की। अब जिला ऊना में भी इसी तर्ज पर खाद का भंडार तैयार किया जाएगा और वहां से प्रदेश के अन्य जिलों में खाद की आपूर्ति की जाएगी।

जैविक खाद में सोलन बन रहा रोल मॉडल

मिशन रीव के तहत बदल रही किसानों की आर्थिकी

टीम रीव, सोलन

आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश को जैविक राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को उनके गांव–घर में ही जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब किसान खाद तैयार कर लेते हैं तो आईआईआरडी उसके लिए बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। इसके चलते गांव में किसानों को अच्छी–खासी आय बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल को जैविक खेती की ओर ले जाने में भी मदद मिल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे कई उदाहरण है जहां आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत जैविक खाद से किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। हाल ही में जिला सोलन में अनेक किसानों को मिशन रीव के तहत जैविक खाद के तहत खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। किसानो ने खाद तैयार की और इसके बाद इस खाद की पैकिंग और खरीददारों तक इसे पहुंचाने का सारा कार्य मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया गया।

इस बार सोलन से चंबा के लिए करीब 2400 किलोग्राम खाद भेजी गई। यह खाद सोलन के मायादत गांव धमकड़ी, ने मिशन रीव के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद तैयार की। इससे पहले भी सोलन से जुब्बल और किन्नौर को जैविक खाद भेजी जा चुकी है। गई। इससे किसानों को परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी और उन्हें घर बैठे आय भी प्राप्त हो गई। मायादत्त ने बताया कि उन्होंने मिशन रीव के तहत ही खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसके बाद खाद बनानी शुरू की।

जब खाद बनाने की शुरूआत की तो मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से समय–समय पर उचित मार्गदर्शन किया गया। इसके बाद जब खाद बनकर तैयार हो गई तो मिशन रीव सचिवालय से मिशन प्रतिनिधियों ने आकर खाद की पैकिंग की और यहीं से खाद उठा ली। इससे मायादत्त को करीब 12 हजार रूपए की अतिरिक्त आय घर बैठे प्राप्त हो गई। न तो खाद के लिए ग्राहक ढूंढने का झंझट हुआ और न खाद को बाजार तक पहुंचाने का।

आईआईआरडी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर न केवल गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत कर रहा है बल्कि प्रदेश की मिट्टी को रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

द रीव टाइम्स

आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है।
इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर
संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636
साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम....
रीव जैविक खाद

खाद में पोषक तत्वों की मात्रा

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

रीव जैविक खाद अब 5,20,40 किलो की पैकिंग में भी उपलब्ध है

जैविक खाद के बाद अब मृदा परीक्षण की सुविधा देगा मिशन रीव

टीम रीव, बिलासपुर

प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए जैविक खाद के बाद एक और अच्छी खबर है। आईआईआरडी मिशन रीव के तहत जल्द ही बिलासपुर में मृदा परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईआरडी शिमला में दिया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने की भी योजना है। लैब में मृदा परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित की जाएंगी जिसमें किसानों को स्टीक और समयबद्ध रिपोर्ट मिल सकेगी।

मृदा जांच क्यों?

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को स्वस्थ रहने में सहायता करती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ मुख्य तत्वों की श्रेणी में आते हैं जबकि कुछ सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं।

मुख्य तत्व

कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम।

सूक्ष्म तत्व

जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लौह, बोरोन, व क्लोरीन। इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है। यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाए तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है।

ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लैकिन उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है।

रीव मृदा जांच के उद्देश्य

मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।

मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अमलीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करना। फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

किसी गांव, विकास खंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदाओं की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना। इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना।

प्रयोगशाला में मृदा की जांच

मृदा जांच के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। यदि मृदा का नमूना ठीक ढंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परीक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों न बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। खेत की मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए।

कांगड़ा में जनऔषधि केंद्रों से मरीजों को लाभ

टीम रीव, कांगड़ा

कांगड़ा में आईआईआरडी की ओर से खोले गए जनऔषधि केंद्रों से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। कांगड़ा के बनूरी, नूरपूर और पंचरूखी में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खुलने से लोगों को काफी लाभ हो रहा है। आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में तीन सौ जन औषधि चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी के तहत कांगड़ा में भी केंद्र खोले गए हैं और यहां पर लोगों को असानी से सस्ती दवाईयां उपलब्ध हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है इन केंद्रों के खुलने से इलाज पर होने वाला खर्च लगभग आधा हो गया है तथा इस तरह के केंद्र सभी स्थानों पर खुलने चाहिए जिससे लोगों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाईयां आसानी से मिल सके।

मिशन रीव से आसान हुआ दूरदराज के गांवों में जीवन

कांगड़ा में गांव तक पहुंचा मिशन रीव

टीम रीव, कांगड़ा

प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि के द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के अलावा गांव के लोग मिशन प्रतिनिधियों से संपर्क कर भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इनका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान उनके घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया। इस दौरान लोगों से पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है और जैविक खेती व मृदा जांच के बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है।

हमीरपुर में लोगों को विभिन्न प्रभागों के तहत मिलेंगी सेवाएं

जिसकी जैसी आवश्यकता, वैसी मिलेगी सेवा

टीम रीव, हमीरपुर

मिशन रीव के संस्करण दो के तहत अब लोगों को विभिन्न डिविजन के तहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मानव जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर मिशन रीव में 10 डिविजन बनाए गए हैं जिसमें लोगों को उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह हमीरपुर में भी गांव के लोग इन सेवाओं का लाभ मिशन रीव के तहत ले सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य डिविजन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जहां प्रदेश में 300 जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है वहीं हमीरपुर के जाहू में भी लोग जनऔषधि केंद्र से सस्ती दवाईयां प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा अगर कोई मरीज अस्पताल से चैकअप करवाकर बाजार से दवाईयां या अन्य उपकरण लाने में असमर्थ है तो मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से इस कार्य में भी सहयोग किया जाएगा।

इसके बाद गांव के लोगों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए कृषि डिविजन बनाया गया है। इसमें मृदा परीक्षण, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण और मांग की आपूर्ति करना शामिल है। इसके अलावा बीज और कृषि उपकरण भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन में सरकारी योजनाओं की जानकारी के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग किया जाएगा।

इसमें पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना, बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटिलिटी सेवाएं उपलब्ध कराना जैसी सेवाएं शामिल है। जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं उन्हें उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन के तहत क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग किया जाएगा। इसी तरह प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया जाएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन में शिक्षा और विभिन्न तरह के प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन में बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।गांव के लोगों की ओर से तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन सहयोग करेगा। इसी तरह संपत्ति प्रबंधन डिविजन और मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन के माध्यम से लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा ज़रुरत का सामान

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिशन रीव की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मिशन रीव के तहत जहां खेतों को रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जैविक खेती की जानकारी दी जा रही है वहीं उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि वह कैसे जैविक खाद तैयार कर फसलों की बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को कृषि करने के लिए जरूरी उपकरण, उत्तम किस्म के बीज भी मिशन प्रतिनिधियों की ओर लोगों को उनके घरों पर ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कृषि में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को कहां और कैसे प्राप्त किया जाए, लोगो को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत उनकी जरूरतों को न केवल पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि के द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बिझड़ी ब्लॉक में पानी के ड्रमों का वितरण किया गया। यह ड्रम बाजार से बेहद कम दाम पर लोगों के घरों तक पहुंचाए गए।

मिशन रीव के इस प्रयास की ग्रामीणों की ओर

रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी कर रहा है मिशन रीव

से भी खूब प्रशंसा की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कोई नहीं था जो घर तक आकर जरूरत का सामान पहुंचाकर दे। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह काम किया जा रहा है जिससे गांव का जीवन भी आसान हो गया है। अपने स्तर पर सुविधाएं देने के अलावा मिशन रीव के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इस बारे में भी मिशन रीव के तहत लोगों को अवगत करवाया जा रहा है।

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages
RURALIZING INDIA-EMPOWERING VILLAGE RIEV
कि दुनिया देखती रह जाए
आओ गांव की बात गांव में करें

लोगों की जरुरतें समझने के लिए विशेष अभियान

स्वयं कर सकेंगे अपनी आवश्यकताओं का आकलन

टीम रीव, मण्डी

मंडी जिला में मिशन रीव संस्करण–दो के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए मिशन प्रतिनिधि गांव–गांव जाकर लोगों से उनकी जरूरतों को पूछेंगे और ऑनलाइन ही उन आवाश्यकताओं का आकलन करेंगे। इसके अलावा मिशन के सदस्यों और गैर सदस्य स्वंय भी ऑनलाइन ही अपनी आवयश्यताओं का आकलन कर मिशन रीव की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें गांव के लोगों को मिशन रीव संस्करण–दो के तहत उन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी जो संस्करण एक में नहीं थी। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि इन सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

संस्करण दो के तहत मिशन रीव का प्राथमिक चरण इसके सदस्य बनने से आरंभ होता है। सदस्य बनने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाईन फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें कुछ आधारभूत औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।

सदस्यता लेने के साथ ही आम जन अपनी चिंताओं को रीव के साथ साझा करने व समाधान के लिए संबद्ध हो जाता है। इसमें उसका परिवार भी सेवाओ के लाभ का पात्र बन जाता है। द्वितीय संस्करण में सदस्यता प्रारुप अब और भी आसान और सरल प्रक्रिया में उपलब्ध है।

सदस्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण क़दम आवश्यकता आकलन का है जो कि आयु विशेष वर्ग को आधार बनाकर तैयार किया गया है। अपनी आयु वर्ग में अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को मात्र एक क्लिक करके समाधान तक की प्रक्रिया को ऑनलाईन देख सकता है। यह इस प्रकार का पोर्टल और ऑनलाईन सेवा है जिसमें समस्या/ आवश्यकता पर क्लिक करते ही सामने उस समस्या के निदान के लिए किस विभाग या योजना से संपर्क करना है, उसका पूर्ण विवरण सामने आ जाता है। यानि समस्या के निदान की प्रक्रिया स्पष्ट रुप से सामने आ जाती है । उसके साथ ही उस सेवा के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का पूर्ण विवरण भी सामने आ जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मध्यस्तता की आवश्यकता ही नहीं रही और ऑनलाईन ही सारी सुविधाओं देखने, समझने और स्वीकार करने की यह एक अनूठी पहल है। शर्तों को स्वीकार करने के साथ ही मिशन रीव के स्वयंसेवक आपकी आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर एक निश्चित समय के अंदर समाधान के लिए अनुबंधित हो जाते हैं।

इसी तरह होगा आयुवर्ग के अनुसार आकलन आवश्यकता आकलन के माध्यम से सभी वर्गो की आवश्यकताओं का आकलन होगा। ये आयु वर्ग हैं: 0–6, 7–12, 13–18, 19–25, 26–35, 36–50, 51–60, 61–70 तथा 71 वर्ष की आयु से उपर का वर्ग। सदस्यता लेने के बाद संबन्धित आयु वर्ग के सदस्य अपनी आवश्यकताओं का आकलन ऑनलाईन कर पाएंगे और आपको मिलेगा अपनी हर समस्या का समाधान।

मृदा परीक्षण से लाभान्वित होंगे किसान

मिशन रीव मंडी में किसानो को देगा सुविधा

टीम रीव, मंडी

मिशन रीव के अंतर्गत गांव में किसानों को मृदा जांच के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए किसानों को गांव में जाकर जानकारी दी जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में जिला शिमला में मिशन रीव के कृषि प्रभाग से शशि किरण ने विकास खण्ड मशोबरा के विभिन्न गांवों का सर्वेक्षण किया और किसानों से बात की। उन्हें मृदा जांच के बारे में पूछा और मिशन रीव द्वारा घर पर ही इस सुविधा को उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। अब इसी तर्ज पर जिला मंडी में भी किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा मिशन रीव के तहत दी जाएगी। इसके लिए गांव में ही विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ ही मृदा परीक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जांच के लिए मिट्टी के नमूने कैसे लिए जाते हैं और जांच के आधार पर मृदा में कैसे पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखा जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मृदा जांच में यह पता लग जाता है कि खेत को किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और किस प्रकार की फसलें खेत में लगानी होगी।

कुल्लू में आसान हुई जैविक खेती की राह

निशुल्क प्रशिक्षण से सैंकड़ों किसानों को लाभ

टीम रीव, कुल्लू

मिशन रीव के तहत कुल्लू की विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर से उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर भी दिया जा रहा है। अन्य जिलों के साथ–साथ जिला कुल्लू में भी लोगों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुल्लू में दो सौ से अधिक किसानों को जैविक खाद का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

कुल्लू की विभिन्न पंचायतों में लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक जैविक खाद के बारे में कई बार सूना था लेकिन यह कैसे बनती है इसकी जानकारी

उन्हें नहीं थी। मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मिशन कुछ पूछना हो तो आईआईआरडी के पंचायत फेसिलिटेटर अपनी ही पंचायत में उपलब्ध हैं जो तुरंत सेवा प्रदान करने को तैयार रहते हैं।

सोलर पंप योजना को लोगों तक पहुंचाएगा मिशन रीव

जानकारी से लेकर पंप लगाने तक में सहयोग करेंगे मिशन रीव प्रतिनिधि

टीम रीव, कुल्लू

अगर आप सरकार की किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी अब आपको मिशन रीव प्रतिनिधि आपके घर पर ही उपलब्ध करा देंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में भी मिशन रीव प्रतिनिधि पूरा सहयोग करेंगे। इसी अभियान के तहत अन्य सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के किसानों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव सहयोग कर रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जिला कुल्लू में भी किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सहयोग किया जाएगा।

क्या है सौर पंप योजना

साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 90 से 100 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

कृषि और बागवानी उपज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल के बजट में 20 करोड़ रुपये से सौर पंप योजना की शुरुआत की है। सौर पंप योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।

इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 90–100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्त्रोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

दरअसल किसान अब तक डीजल या बिजली से चलने वाले पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं। इससे कृषि की लागत बढ़ती है। बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट पर भी लागत अधिक आती है। अब सौर पंप योजना से प्रदेश के करीब दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत सौर पंपों से सिंचाई के लिए पानी को उठाया जाएगा।

सौर पंप योजना का लाभ

सौर सिंचाई योजना में हिमाचल प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत किसानों को पंप सेट खरीद पर 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी। हिमाचल सरकार किसानों के छोटे और सीमांत श्रेणी/किसान विकास संघ/पंजीकृत निकाय के किसान समूह को सोलर पंप सेट पर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी।

जरुरी दस्तावेज

हिमाचल प्रदेश में निवास का स्थाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जमीन के दस्तावेज और वोटर आईडी।

मिशन रीव के तहत चंबा में तैयार होगी जैविक खाद

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

टीम रीव, चम्बा

हिमाचल की मिट्टी को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन रीव के तहत हिमाचल के किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को जैविक खाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर मिशन रीव के तहत जैविक खाद का भंडार तैयार किया गया है। जिला चंबा में भी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जल्द ही चंबा के किसानों के पास भी जैविक खाद का अपना भंडार होगा। फिलहाल चंबा के लिए किसानों की मांग पर जिला सोलन से मिशन रीव के तहत 2360 किलोग्राम जैविक खाद पहुंचाई गई है। मिशन रीव के इस प्रयास से किसान काफी खुश है।

उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव – गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और उनसे खरीदकर मिशन रीव के तहत उन्हें खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया

सोलन से चंबा पहुंचाई गई 2360 किलोग्राम खाद

गया है। इसी योजना के तहत जिला सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को चंबा और किन्नौर में किसानों की मांग के मुताबिक मुहैया करवाया गया।

किसानों का कहना है कि गांव में जैविक खाद को लेकर अपार संभावनाएं हैं क्योंकि गांव में कृषि और पशुधन ही लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऐसे में किसान जहां अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकेंगे वहीं इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

आओ कानून को जानें

बाल श्रम या बाल मजदूरी क्या है

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है । बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है ।

जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता–पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम्भिक कार्यों में मदद कराते हैं । एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरुरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रुप है । बंधुआ मजदूरी का अर्थ, माता–पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायेगी के कारण, कर्ज के भुगतान के लिये बच्चों को मजदूरों के रुप में कार्य करने के लिये मजबूर करना है ।

बंधुआ मजदूर की अवधारणा से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुये व्यतीत कर देते हैं ।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है:

- परिवार के साथ – बच्चे घर के कार्यों में बिना किसी वेतन के लगे होते हैं ।
- परिवार के साथ पर घर के बाहर – उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर, घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर आदि ।
- परिवार से बाहर– उदाहरण के रुप में, व्यवसायिक दुकानों जैसेः होटलों में बच्चों से कार्य कराना, चाय बेचने का कार्य कराना, वैश्यावृति आदि।

बाल मजदूरी के बढ़ने के कारण

अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र है ।

अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता–पिता, सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार ये बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन का नेतृत्व करता है जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को करने के लिये तैयार नहीं होते ।

राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिये बच्चों को भर्ती करती है जो बिल्कुल अनैतिक है ।

- भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिये बनाये गये प्रारम्भिक कानून जब बना तब बाल रोजगार अधिनियम 1938 पारित हुआ । ये अधिनियम बड़े दुखान्त अंत के साथ असफल हुआ । इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण गरीबी का होना था क्योंकि निर्धनता बच्चों को मजदूरी करने के लिये मजबूर करती है।
- भारतीय संसद ने बाल श्रम या मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर कानून और अधिनियम पारित किये हैं । 14 साल की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदानों में या खतरनाक रोजगारों (जहाँ जान जाने का ज्यादा जोखिम हो) में बाल मजदूरी को निषेध करने के लिये हमारे संविधान में अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है । इसके अलावा, अनुच्छेद 21 को अन्तर्गत, ये भी प्रावधान किया गया है कि, एक राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा के लिये सभी आधारिक संरचना और संसाधन उपलब्ध करायेगा।
- संविधान के तहत बच्चों की बाल श्रम से सुरक्षा का नियमन करने के वाले कानूनों का एक समूह मौजूद है । कारखाना अधिनियम 1948, 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है । खदान अधिनियम 1986, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों का खदानों में काम करना निषेध करता है ।,
- बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं नियमन) 1986, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में, जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गयी सूची में शामिल किया गया है, में काम करना निषेध करता है। इसके अलावा, बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है ।

बाल मजदूरी से लड़ने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

बाल मजदूरी के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी.एल.), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अन्तर्गत 1991 में, बाल मजदूरी के बारे में जागरुकता का निर्माण एक वैश्विक मुद्दे के रुप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करके, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये शुरु किया गया था । भारत बाल श्रम का मुकाबला करने में मदद करने के लिए आई.पी.ई.सी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राष्ट्र था ।

राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम (एन.सी.एल.पी.), उन मुख्य कार्यक्रमों में से एक है जो पूरे देश में शुरु किया गया था जिसमें वर्ष 1988 में, सात बाल श्रम कार्यक्रम शुरु किये गये थे । पुर्नवास, भारत सरकार द्वारा, भारत में बाल श्रम की घटनाओं को कम करने के लिये अपनायी गयी प्रमुख नीतियों में से एक है ।

बाल मजदूरी का कैसे उन्मूलन करें

बच्चों के अवैध व्यापार का अंत, गरीबी का उन्मूलन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और जीने का सामान्य स्तर, बड़े स्तर पर समस्या को कम कर सकता है । विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गरीबी के उन्मूलन के लिये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके मदद करते हैं ।

दलों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण को रोकने के लिये श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान बाल श्रम निषेध कानूनों को कड़ाई से लागू करके स्थिति को नियंत्रित करने के लिये बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है । निम्नतन सीमा 14 साल को कम से कम 18 साल तक बढ़ाने की आवश्यकता है । जोखिम वाले कार्यों की सूची जो वर्तमान में कानून के अन्तर्गत है, उसमें और अधिक व्यवसायों को शामिल करने की आवश्यकता है जिन्हें खतरनाक गतिविधियों के दायरे से बाहर रखा गया है ।

लोकसभा ने 26 जुलाई 2016 को बालश्रम निषेध और विनियमन संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया । संशोधित विधेयक में सभी व्यवसायों या उद्योगों में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित किया गया है ।

संशोधन के मुख्य तथ्य–

- इस विधेयक के अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना संज्ञेय अपराध माना जायेगा ।
- इसके लिए नियोक्ता के साथ–साथ माता–पिता को भी दंडित किया जाएगा ।
- विधेयक में चौदह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है ।
- इस आयु वर्ग के बच्चों से किसी खतरनाक उद्योग में काम नहीं कराया जाएगा ।
- किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि छह महीने से दो साल तक बढ़ा दी गयी है ।
- अभी तक इस अपराध के लिये तीन महीने से एक साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था ।
- जुर्माना बढ़ाकर बीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक कर दिया गया है ।
- दूसरी बार अपराध करने पर एक साल से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

ऑफिस में ऐसा करने से खराब हो सकती है आपकी इमेज, इन बातों का रखें ध्यान

द रीव टाइम्स ब्यूरा

वर्कप्लेस और घर एक जिंदगी के दो हिस्से होते हैं। दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर जैसा व्यवहार ऑफिस में करें और घर पर ऑफिस जैसा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आदतें आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती हैं। खास तौर पर तब, जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपका काम परफेक्ट है और आप ऑफिस में कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं।

- याद रखें कि आपकी हर एक गतिविधि का असर आस–पास रहने वाले लोगों पर पड़ता है। आप काम में कितने ही अच्छे क्यों न हों, आपकी आदतें सही न हो तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पर जोर दें और कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा ही राइट साइड पर रखें। इसका फायदा आपको उम्र भर मिलता ही रहेगा।
- ऑफिस में ऑनटाइम रहना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। कभी–कभी आप लेट हैं, तो यह चल जाता है। लेकिन देरी से ऑफिस पहुंचना आपकी आदत बन जाए, तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। हर रोज एक्सक्यूज काम नहीं आते। आप वास्तव में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और इस वजह से देरी से ऑफिस पहुंच रह रहे हैं, तो इस बारे में अपने बॉस को ज़रूर बताएं। वर्कप्लेस पर वर्किंग आवर इसलिए निर्धारित किए जाते हैं, ताकि सबके लिए समान अनुशासन लागू किया
- वर्कप्लेस पर गॉसिप से खुद को दूर रखें। जब आप धीरे–धीरे अपने साथी से बात करते हैं या उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, तो साथियों को यह लगता है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर उनकी बात कर रहे हैं। इससे साथियों के मन में नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। यह आपकी इमेज को खराब करने के लिए काफी है।
- वर्कप्लेस पर टेक्नॉलजी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। फोन स्मार्ट फोन का रूप ले चुके हैं और एप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद कई बार आपको बात करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस में बात करते समय अपनी आवाज को धीमा रखें। आप रिंगटोन और उसकी आवाज को लेकर भी सतर्कता बरतें। वरना यह वर्कप्लेस पर बाकियों को डिस्ट्रैक्ट और इरिटेट करता है। आपको बार–बार बात करना पड़ रहा है, तो आप कॉन्फ्रेंस रूम का इस्तेमाल करें।
- ऑफिस और घर में अंतर होता है। आप घर पर चाहे जैसे भी रहते हों, लेकिन ऑफिस में आपको अपने डेस्क और केबिन को साफ–सुथरा रखना होता है। यह आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी बात होती है। इसके लिए आप डेस्क मैनेजमेंट की क्वॉलिटी को अपने भीतर शामिल करें। आपका डेस्क सही नहीं है, तो इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ये बातें आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालती हैं। इसलिए इनका ध्यान रखें।
- आपने नई कंपनी जॉइन की है और आपको वहां का वर्किंग कल्चर या जॉब प्रोफाइल रास नहीं आ रहा है, तो इसकी चर्चा अपने सहकर्मियों के साथ कभी न करें। अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों से इसकी चर्चा कर सकते हैं। उनकी राय ले सकते हैं। जैसे ही आपके सहकर्मियों के बीच यह मैसेज जाता है कि आप इस जॉब को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यह सही नहीं होता है। यह आपकी पर्सनैलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
- ऑफिस और बॉस के प्रति ईमानदारी बरतने की आवश्यकता रहती है। आप जिस कंपनी अथवा अन्य में अपनी सेवाऐं दे रहे हैं, वहां के प्रति आपके कार्य एवं दक्षता में एक पैशन होना चाहिए। आपकी ईमानदारी भी आपके व्यवहार एवं सेवाओं के लिए आपके व्यक्तित्व में वृद्धि का कारक होती है।

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

सर्वाइकल पीड़ा...लक्षण एवं उपचार

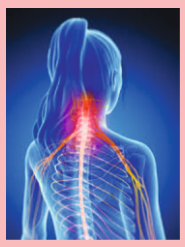

इन दिनों कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कुछ साल पहले तक किसी बीमारी की श्रेणी में गिनी ही नहीं जाती थी, जो अब बड़ी तकलीफ बनकर खड़ी हो जाती हैं, जी हां जॉइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन जैसी शरीरिक तकलीफें ऐसी दर्दनाक होती हैं, जिसे देखने वाला समझ नहीं पाता और झेलने वाला इसके दर्द को बयान नहीं कर पाता । इस अंक में इन्हीं बीमारियों में से एक सर्वाइकल पेन की बात कर रहे हैं ।

- यह समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों, गरदन आदि में भयानक दर्द होता है जिसे हम सर्वाइकल का दर्द कहते हैं । यह समस्या किसीको भी हो सकती है । आज के दौर में अव्यवस्थित दिनचर्या और अनियमितताओं के कारण लगभग हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की परेशानी सहनी पडती हैं।
- घंटों बैठे रहना, खराब पोश्चर, झुक कर बैठना और कई अन्य गलत आदतों की वजह से इस परेशानी का सामना बड़ी तादाद में लोगों को करना पड़ता है पर हमें अपनी आदतों या इससे बचने के उपाय नहीं मालूम होते इसलिए हम सभी को सर्वाइकल दर्द की वजह, लक्षण और इसके आसान घरेलू उपचार की जानकारी होनी बहुत जरूरी है ।

सर्वाइकल पेन के कारण

- गलत पोजीशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है ।
- ज्यादातर लोगों को भारी वजन को सिर पर उठाने से सर्वाइकल पेन होता है ।
- गर्दन को बहुत देर तक झुकाये रखने से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है ।
- बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है ।
- ऊंचे और बड़े तकिये का प्रयोग करने से सर्वाइकल पेन होता है ।
- भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है ।
- गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है ।

सर्वाइकल पेन के लक्षण

- सिर का दर्द
- गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के टिडक्ने के जैसी आवाज का आना ।
- हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना ।
- व्यक्ति को हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना।
- गर्दन और कंधों पर अकड़न होना

कुछ हिदायतें :

1. सही ढंग से सोएं
2. गर्म और ठंडा सेख
3. मसाज
4. खूब पानी पियें
5. स्ट्रेस से बचें
6. राइट डे शेड्यूल अपनाएं
7. स्ट्रेच एक्सरसाइज की आदत डालें

जरुरी आदतें

दोस्तों सर्वाइकल पेन के कारण, लक्षण और इलाज जानने के साथ ही आपको कुछ आदतें छोड़नी और कुछ आदतें जरूरी तौर पर अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करनी होंगी जैसे कि :

- ज्यादा वजन वाले सामान उठाने की आदत छोड़ दें।
- वज्रासन, चक्रासन और मत्स्यासन के अलावा गर्दन को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करे।
- प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर कम से कम 3 किलोमीटर तेज रफ्तार से पैदल चलें।
- अपने ऑफिस में ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में न बैठकर हर एक घंटे के बाद थोड़ी–थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर थोड़ा वाक करने की आदत डालें।
- अगर आप घरेलू महिला है तो ज्यादा देर न सोये और घरेलू कार्यों के बीच थोडा थोडा ब्रेक ले कर आराम करें।
- बैठ कर फर्श पर पोछा लगाने का शौख पालें इससे काफी आराम मिलेगा।
- ध्यान रहे यह शुरुआती तकलीफ के लिए बेहतर उपाय हैं लेकिन अगर तकलीफ से राहत ना मिले तो तुरन्त डॉक्टर से संपर्क करें।

दवाईयों का सेवन और उपचार अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करें।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला

अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

पर्यावरण अंततः चर्चा का विषय ही क्यों बने, एक्शन का क्यों नहीं

पर्यावरण लगभग पिछले दो दशकों से वैश्विक चर्चा का अहम विषय बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते, कार्यक्रम तथा आयोजन होते रहे। कार्यक्रमों को जीवन यापन की पद्धति (लाइवलीहुड) से जोड़कर अभी तक के सबसे बड़े वित्तपोषी कार्यक्रमों में स्थान मिला । समृद्ध देशों ने कार्बन उत्सर्जन के समाधान के लिए विकासशील देशों को वनीकरण बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास किए ताकि विकसित देशों में स्थित उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड विकासशील देशों में तैयार हो रहे जंगल सोख सके। लेकिन ऐसे प्रयास लगभग 8–10 वर्षों के अंतराल में सिकुड़ते गए। भारत सरकार ने भी जलागम (वाटरशैड डेवेलपमैंट) परियोजना जैसे कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से लोगों की रोजी–रोटी को जोड़ते हुए आरंभ किए लेकिन परियोजनाओं के सरकारीकरण से यथेच्छा परिणाम नहीं मिल सके। देश में विकास की गति का पहिया बढ़ने लगा तथा ढांचागत व्यवस्था बदलने लगी। चौड़ी सड़कें, बहुमंजिली इमारतें व उद्योगो आदि का विस्तार होने लगा हैं। ऐसे में जंगलों पर सबसे अधिक दबाव बढ़ने लगा तथा अनगिनत संख्या में पेड़ कटने लगे, जिनका कटना अपरिहार्य भी है। लेकिन इनके बदले पेड़ों को लगाने, बचाने तथा बड़ा करने का पहलु दृष्टिगोचर होता नहीं। हर परियोजना में पर्यावरण स्वीकृति इस शर्त पर मिलती है कि परियोजना से होने वाले पर्यावरण की नुकसान की भरपाई अधिक पेड़ लगाकर हो। इस कार्य हेतु वन विभाग के पास हरवर्ष करोड़ों रुपये जमा भी होते हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग का अपना भी वनीकरण का वार्षिक बजट होता है। केन्द्र सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय से आने वाली धनराशि अतिरिक्त होती है । इस राशि को खर्च करने के लिए भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों का एक बड़ा दल प्रयुक्त है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पहाड़ियां नंगी होती जा रही हैं। पेड़ों के बाहुल्य के विपरीत वनाच्छादित भूभाग व्यवहारिक दृष्टि से कम होता जा रहा है, यदि सरकारी आंकड़ों की अनदेखी करें तो। हर वर्ष लाखों पौधें व पंछी वनाग्नि का शिकार हो जाते हैं और अभी तक हमारे पास इसका सामना करने का कोई उपाय नहीं हैं। वन माफिया आज भी हज़ारों की संख्या में चुपचाप पेड़ काटकर जंगल के जंगल साफ कर रहा है। इसका खुलासा हाल ही में शिमला के ननखड़ी क्षेत्र से चोरी हुई लकड़ियों की तहकीक़ात से हुआ, जहां पता चला कि जम्मू–कश्मीर के कुछ चीरानी कई वर्षों से इस गोरखधंधें में लिप्त हैं। लेकिन कार्यवाही के नाम पर व्यवस्था के पास किंतु–परंतु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आख़िर ये सब बातें हमें दिखती क्यों नहीं? तथा हमारे मस्तिष्क को झकझोर क्यों नहीं देती? क्या यह हमारी संवदेनहीन मानसिकता का परिणाम है ? या बाड़ ही चोरी करना सीख गई है, ये प्रश्न जस के तस बने रहेंगें । प्रदेश में वनीकरण को सतत विकास तथा जवाबदेही के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को विभागीय परिधि से कुछ बाहर निकालकर जनमानस के लाभ के साथ सम्मिलित करना होगा। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में वनों की निशानदेही का कार्य करने के बाद वनीय भू–भाग को श्रेणीवार बांटा जा सकता है, जैसे कि समृद्ध, घना जंगल, पतला जंगल, बिना पेड़ का भूभाग आदि। पंचायत में ही 10–15 ऐसे साधन विपन्न परिवारों का चयन किया जा सकता है जो खाली जगह तथा पतले जंगल को घने जंगल में परिवर्तित करने का माद्दा रखते हैं। चयनित भूभाग को पांच वर्षों तक देख–रेख के लिए अनुबंध करके सौंपा जा सकता है और उनका वार्षिक मानदेय मनरेगा से जोड़कर व्यवस्थित किया जा सकता है।

डा. एल.सी. शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

The Journey Continues ...

"You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it's important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages". -- Michelle Obama

When we look back at Mission RIEV one-year journey, that's exactly what we did. The challenges were never perceived as a disadvantage, instead of overcoming them and converting them into opportunity was our prime objective. And you, we didn't fail. At the same time, we didn't succeed fully but there's a sense of satisfaction amongst us that we were able to make a visible impact in people's life. In the initial phase, we focussed upon enrolling members for Mission RIEV and within few months we had around 3000 plus registered members. It may be noted that initially we had a few services to offer them but it's the confidence and the belief of people on us that made us work even harder. Not only did we provide services such as pathological tests and very competitive rates at the doorsteps of people, we also mobilized people from villages to convert their bio-waste into a sustainable business model. Today, we can proudly say that we have conducted more than 5000 pathological tests, identified major lifestyle diseases and provided medical advises and medicines through our 12 Generic Medical Outlets. Over and above, we have created a stock of more than 150000 kg of organic manure, all this under buy-back scheme, wherein we invest and share the tech-knowhow with people and create an ecosystem wherein not only we develop a sustainable business model but also create awareness against rampant usage of chemical fertilizer in the State...a small step towards the larger goal of making the farming and the farmland environmental-friendly and an organic State. Not to forget the employment opportunity given to more than 3000 youths of the State. Mission RIEV through its initiatives saw more than 30% of youths doing reverse migration from cities to their respective villages. And are they feeling proud of it... your guess is as good as mine.

This doesn't take away the challenges we faced such as 1) Managing large human resources 2) Implementing various initiatives 3) Monitoring the implementation of initiatives and the most challenging 4) Resource mobilization 5) Mud slugging by vested interest, which included few media houses.

Lesson learned... that too, a hard way!! Where we perturbed, not at all. Our resolve got even stronger and on September 15, 2018, we announced the Version 2 of Mission RIEV, which was successfully launched on 2nd October 2018, the founding day of Mission RIEV.

The journey of Mission RIEV can be best described by quoting famous couplets of Majhrooh Sultanpuri...

मैं अकेला ही चला था जानिब–ए–मंज़िल मगर
लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया

What is there in Version 2 of Mission RIEV? Well, it comes with complete transparency, complemented by a robust IT platform and user-friendly interface. Each employee under Mission RIEV Version 2 will have either a tablet, laptop or desktop to work. His work and efforts will instantly get reflected on the dashboard. The ownership of the gadget shall be theirs (T&C applies) and through this, they will be providing 10 types of services such as health, property management, rural market produce, banking & finance, agriculture, education, utility & license, online services, entrepreneur & business development, publishing & printing. All these after getting the need assessment of each member of the family. Over and above this, people now have an option of becoming a Paid Annual Member, Life Member or Voluntary Membership which is for free. Each of these categories gives many benefits and few of them are for free too. With new, dynamic and robust platform which includes portal. gives complete transparency on the functioning of Mission RIEV Version 2. Needless to say, our entire team is excited and are already in the field. There's much to what I have mentioned here and many more to come in near future. Come, check and browse our new portal www.missionriev.in ... it's a world of opportunity waiting for everyone... come and be part of this journey. And for those who have left us for whatever reasons, we welcome you all and together let's make a difference in people's life. It's just a beginning... let's take a small step towards serving humanity as a whole.

I would like to end my note with a famous quote from Helen Keller -- "Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved."

That's Mission RIEV V2 for you. Come, be part of 21st centuries renaissance!!

Anand Nair, Managing Editor
anand@iirdshimla.org

सेब–किन्नू से तपोवन में विधानसभा सत्र की राजनीति तक

दो विधानसभा परिसर जरुरत से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी

पांच से छह दिन के शीतसत्र में खर्च हो जाते करीब एक करोड़

नेताओं –नौकरशाहों की आवभगत और सुरक्षा पर ही खर्च हो जाता है लाखों

अंजना ठाकुर (सहायक संपादक)
anjna@iirdshimla.org

हिमाचल प्रदेश में ऊपरी हिमाचल व निचला हिमाचल, शिमला व कांगड़ा तथा सेब और किन्नू के नाम पर लंबे समय से खूब राजनीति होती रही है। वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की शुरूआत कर इस खाई को पाटने का प्रयास किया गया। दावा किया गया कि धर्मशाला में सत्र की शुरूआत ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल के बीच भेदभाव के मिथ को तोड़ेगी। कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, और साथ लगते जिलों के लोगों और सरकार के बीच की खाई पाटना तपोवन में शीतसत्र आयोजित करने के पिछे सबसे बड़ा तर्क रहा था। लेकिन आज 12 साल बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि तपोवन में विधानसभा सत्र की परंपरा को निभाना जरूरत से कहीं ज्यादा हर सरकार की मजबूरी बन गई है। समय – समय पर बड़े नेताओं के भी बयान आते हैं कि तपोवन में विस भवन का प्रयोग सत्र के साथ ही किसी अर्थपूर्ण कार्य के लिए भी किया जाना चाहिए।

पुर्व में विधानसभा के ही एक सत्र के दौरान तत्कालीन विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर कितना खर्चा होता है। इस पर जो जवाब आया उससे जनप्रतिनिधियों को भले हैरानी न हो लेकिन आम आदमी को हैरान – परेशान करने के लिए यह आंकड़ा काफी था। जानकारी के मुताबिक इंद्र सिंह के सवाल पर सरकार ने तीन सालों का आंकड़ा दिया और लिखित जवाब देते हुए बताया कि विधानसभा शीत सत्र के दौरान हर साल औसतन एक करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो रहे हैं। हिमाचल सरकार पांच से छह दिन के शीतकालीन सत्र पर ही हर साल औसतन 1 करोड़ 43 लाख का खर्च करती है। सरकार ने बताया कि तीन वर्षों में शीतकालीन सत्र पर 4 करोड़ 31 लाख का खर्च किया है। इसमें जीएडी से लेकर रहने, खाने और सुरक्षा सभी का खर्च शामिल थ। इसमें रहने और खाने पर ही 2013 में 1 करोड़ 35 लाख 21 हजार 982, वर्ष 2014 में 1 करोड़ 11 लाख 22 हजार 654 और 2015 में 92 लाख 47 हजार 886 रुपये खर्च किए हैं। सुरक्षा पर वर्ष 2013 में 11 लाख 91 हजार 104, वर्ष 2014 में 11 लाख 37 हजार 694, 8 लाख 51 हजार 934 रुपये खर्च किए हैं। वाहनों पर वर्ष 2013 में 18 लाख 89 हजार 373, वर्ष 2014 में 20 लाख 293 रुपए, 19 लाख 01 हजार 778 रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ–साथ यात्रा और दैनिक भत्ते पर वर्ष 2013 में 1 लाख 11 हजार 482, 2014 में 1 लाख 17 हजार 781 और वर्ष 2015 में 1 लाख 02 हजार 46 रुपये खर्च किए हैं। कुल मिला कर हर वर्ष धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन करने में सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीबीएल बुटेल ने मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि, "तपोवन स्थित विधानसभा भवन परिसर का फायदा तभी है जब इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। उन्होंने कहा कि वर्ष में सिर्फ दो– चार दिन विधानसभा सत्र आयोजित होने से इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है।" अभी हाल ही 10 से 15 दिसंबर तक तपोवन में विधानसभा के शीतसत्र का आयोजन किया किया। कई प्रस्ताव पास हुए, चर्चाएं भी हुई लेकिन यह भी सच है कि जनता के एक करोड़ के मुकाबले यह एक अर्थहीन कवायद है। यह सभी कार्य इससे आधे खर्च में भी किए जा सकते थे। उल्लेखनीय है कि तपोवन में एक सेशन आयोजित करने पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च आता। मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों सहित पूरी सरकार को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना पड़ता है। बीते कुछ वर्षों के आकलन में पाया गया कि इस खर्चीली कवायद का वहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के नाम पर मात्र औपचारिकताएं ही निभाई जाती रही हैं। धर्मशाला में विधानसभा सत्र को सही ठहराने के लिए कई बार जम्मू– कश्मीर का उदाहरण सामने रखा गया। इस बात को नजरंदाज किया गया कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश और जम्मू– कश्मीर की परिस्थितियां समान नहीं हैं। जम्मू से श्रीनगर की दूरी बहुत अधिक है। श्रीनगर (कश्मीर) में बहुत बर्फ गिरती है और ठंड भी बहुत होती है। ऐसे में वहां दो विधानसभा परिसर होना गलत नहीं है। लेकिन शिमला और धर्मशाला में दूरी इतनी ज्यादा नहीं है और ठंड भी लगभग बराबर ही पड़ती है। जम्मू– कश्मीर में दो विधानसभा सत्र भौगोलिक परिस्थितिवश एक मजबूरी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह मात्र राजनीतिक मजबूरी।

स्मार्ट सिटी से पहले की प्राथमिकता स्वच्छता की है

सबसे अधिक अस्वच्छता कुत्तों एवं बंदरों की गंदगी से है

हेमराज चौहान (सहायक संपादक)
chauhan.hemraj09@gmail.com

शिमला में आवारा कुत्तों एवं बंदरों के अलावा पालतु कुत्तों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्वच्छता का वातावरण बन चुका है। समय–समय पर प्रशासन के बयान और कार्यवाही की ख़बरें तो सुनी जाती हैं लेक़िन हकीक़त में कार्यवाही के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। शिमला के रास्तों पर चलना तक मुश्किल हो रहा है। लोगों ने पालतु कुत्तों के लिए रास्तों एवं पार्क अथवा सार्वजनिक स्थानों को गंद करने के लिए चयनित किया हुआ है। इससे सारा गंद कहीं न कहीं वर्षा आदि के पानी के साथ मिलकर प्राकृतिक स्रोत एवं पीने के पानी के स्रोतों में मिलकर इसे दूषित कर रहा है।

यह बात समय–समय पर हमेशा उठती रही है कि शिमला में आवारा एवं पालतु कुत्तों की समस्या का समाधान प्रशासन / नगर निगम समय रहते करे, किंतु नगर निगम इसमें कामयाब नहीं हो पाया। कुछ समय के लिए कभी–कभार गाड़ियों में मॉल रोड़ और रिज़ पर आराम फरमाते कुत्तों को पकड़कर कहीं ले जाया जाता है और बाद में वही आवारा कुत्ते रिज और मॉलरोड़ पर ही फिर से आराम फरमाते मिल जाते। अब तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि शिमला में पर्यटकों को दिक्कत हो ही रही है साथ ही यहां के बाशिंदों को भी अब इस समस्या से दो–चार होना पड़ रहा है ।आए दिन लोगों को काटने के मामले सामने आते हैं। मॉल और रिज पर तो कुत्तों का गंद न केवल यहां की सुंदरता की पोल खोलता है अपितु स्वच्छता के प्रति सरकार और नगर निगम के रवैये को भी दिखाता है। हालांकि सफाई कर्मचारी सारा दिन रिज पर घोड़ों और कुत्तों की गंदगी को साफ करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। परन्तु क्या समस्या का निदान यही है कि इन आवारा कुत्तों को रिज और मॉल रोड़ जैसे पॉश इलाकों में अपना अड्डा बनाने दिया जाए और उनके द्वारा फैलाई जा रही हरतरफ की गंदगी को साफ करने के लिए कर्मचारी की मुस्तैदी सारा दिन रहे ।

पालतु कुत्तों से शिमला परेशान, लोगों का शौक सबके स्वास्थ्य के लिए पड़ रहा है भारी

आवारा कुत्तों के अलावा पालतु कुत्तों से भी शिमलावासी और पर्यटक अब बेहद परेशान हो चुके हैं। पालतु कुत्तों को पालने का शौक शिमला की स्वच्छता पर कलंक की तरह है जिसका ख़ामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है ।इन पालतु कुत्तों के मालिक विभिन्न प्रजातियों के मंहगे कुत्तों के साथ सुबह से शाम तक शिमला की सड़कों एवं रास्तों पर टहलने और घुमाने तथा सड़क के बीचोबीच उनसे गंदगी करवाकर अपने रुतबे को दिखाते हैं। फिर वही जहां – तहां वो गंद राह चलते लोगों के जुतों, गाड़ियों आदि से घर और दफ़्तरों आदि में पंहुचता है। इतना ही नहीं सुबह ही स्कूल जाते बच्चों को रास्तों में इस गंदगी से पार पाना मुश्किल हो जाता है। यही गंदगी पानी में मिलकर पानी के स्रोतों को ज़हरीला और दूषित कर रही है। इस पानी से किस प्रकार पूरे शिमला को अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पानी के गंदा होने और पीलिया के मुख्य कारकों में एक मुख्य और बड़ा कारण यह भी है। इस बात को नगर निगम और शिमला में बैठी सरकार भलिभांति परिचित है। फिर भी समस्या के निदान हेतु कोई कारगर और गंभीर क़दम अभी तक नहीं उठाया गया ।

पालतु कुत्तों के मालिकों को लगाया जाए टैक्स

पालतु कुत्तों को पालने वाले शौकीनों को टैक्स देने के लिए नगर निगम कोई उचित क़दम उठाए। इन शौकीनों के कारण पूरे शिमलावासियों एवं यहां आने वाले दुनियाभर के पर्यटकों को गंदगी एवं पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। और ये शौकीन अपने रंग – बिरंगी प्रजातियों के इन कुत्तों को सड़क पर बड़ी शानोशौक़त से घुमाते हुए सड़क के बीच में ही गंदगी करवाते हैं। नगर निगम को अब इसके लिए कारगर क़दम उठाने चाहिए और पालतु कुत्तों पर टैक्स लगे ताकि सड़क, रास्तों आदि में पूरा दिन की जा रही गंदगी को रोका जा सके। यह जिम्मेवारी भी कुत्तों के मालिकों की है कि यदि कुत्ता सार्वजनिक स्थानों में गंदगी करता है अथवा रास्तों एवं सड़क पर भी तो उसे साफ भी उसे ही करना है ।

बंदरों का आतंक ही नहीं गंदगी भी परेशानी का सबब

यही हाल शिमला में बंदरों की संख्या में हो रही बढ़ौतरी से भी हो रहा है । ऐसा नहीं कि बंदरों से शहरवासियों एवं पर्यटकों को मात्र ख़तरा ही है, उनसे हो रही गंदगी भी पानी को दूषित कर रही है। शिमला में ऐसे कितने ही स्थान है जहां पानी की टंकियों के ढक्कन खोलकर या तोड़कर उसमें बंदर उछलकूद करते रहते हैं और वही जल लोग उपयोग में ला रहे हैं। एक लंबे समय तक ज़िलाधीश कार्यालय के पास भी लगी सभी टंकियों में बंदर गंदगी करते, नहाते और उसी जल को उपयोग में लाया जाता। ऐसा शिमला के अनेक स्थानों में हो रहा है। बंदरों की गंदगी भी हर घर, छत, सड़कों, रास्तों, पानी की टंकियों, जलटैंक आदि पर समस्या को गंभीर बना रहा है। यही गंदगी अंततः जल स्रोतों में घुलती है और सबकी परेशानी का कारण बनती है।

सीवरेज व्यवस्था भी हो दुरुस्त

आए दिन शिमला में स्वच्छता की पोल खोलते सीवरेज के गड्ढे और जहां–तहां से टूटी हुई पाईपों के कारण चलना भी दुभर हो गया है। सीवरेज व्यवस्था आरंभ से ही शिमला की सबसे बड़ी कमज़ोरी कही जा सकती है जिसे आज भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है। पुरानी सीवरेज की पाईपें, ब्लॉकेज आदि से सड़कों एवं रास्तों पर कई बार गंदगी की बाढ़ आ जाती है और शिमला में चलना भी दुभर हो जाता है। यह भी पानी से मिलकर जलस्रोतों में घुल जाती है।

कोई ठोस एवं कारगर नीति अब तक नहीं

दरअसल, समस्या यह है कि नगर निगम किसी ठोस नीति अथवा योजना के साथ अभी भी काम नहीं कर रहा है। पिछली नगर निगम के आकाओं के पास इस समस्या का जो समधान था, वो सिरे नहीं चढ़ पाया और अभी की नगर निगम इस पर कुछ न कुछ समाधान करने की बात करती रहती है। बंदरों की नसबंदी, जलटैंकों को ढकने, आवारा कुत्तों को पकड़कर शिमला से बाहर करने आदि फॉर्मुले पर चर्चाऐं होती रहती हैं..... पर ये चर्चा समाधान तक नहीं आती है यानि इसका व्यवहारिक रुप अभी तक शिमलावासियों को देखना बाकि है।

स्मार्ट सिटी के मायने कंकर पत्थर की सजी दीवारों से कहीं अधिक उस सिटी के रहने वालों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन, शहर की स्वच्छता, साफ – सफाई आदि से होते हैं। संगमरमर की दीवारें ही शहर को स्मार्ट नहीं बनाती, उसे स्मार्ट बनाने के लिए हुक्मरानों की कारगर नीतियों एवं जनहित, जनरक्षक योजनाओं को बनाकर अमलीजामा पहनाकर यथार्थ में उतारने से होती है।

अश्विनी खड्ड का मामला: दो महीनों में शिमला की प्लास्टिक नदी के सफाई का आदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के शिमला में महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत अश्विनी खड्ड के प्लास्टिक कचरे वाली नदी में तब्दील हो जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी ज़ाहिर की है।

पीठ ने अगली सुनवाई में शिमला नगर निगम के कमिश्नर और सोलन नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तलब किया है। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया है ।

पीठ ने कहा कि अश्विनी खड्ड से जुड़ने वाले छोटे–बड़े सभी नालों में ऐसे जाल लगाए जाने चाहिए जो ठोस कचरा समेत प्लास्टिक कचरे को खड्ड पहुंचने से पहले ही रोक लें ।

पीठ ने फटकार लगाते हुए ये कहा

एनजीटी ने कहा कि शिमला नगर निगम और सोलन नगर पालिका अश्विनी खड्ड की पूरी तरह सफाई करने के बाद आदेश अनुपालन की रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करें । एनजीटी का यह आदेश हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) की तरफ से ट्रिब्यूनल में दाखिल हलफनामा पर आया है । पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में उनके पास चार महीने देरी से रिपोर्ट दाखिल की गई । पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में अगले वर्ष 28 फरवरी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है । वहीं मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 मार्च को होगी ।

हिमाचल विधानसभा में गोवंश संरक्षण सहित चार विधेयक पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धर्मशाला में शीत सत्र के पांचवें दिन सदन में विपक्ष के विरोध के बीच गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक पारित हुआ।

इसके अलावा नशे के खिलाफ सख्ती बरतने वाला संशोधित एनडीपीएस, चिट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों के हित का संरक्षण संशोधन विधेयक और जीएसटी संशोधन बिल विधानसभा में चर्चा के बाद बहुमत से पारित कर दिए गए।

अब ये विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजे जाएंगे। इसके बाद कानून का रूप ले लेंगे। सदन में विपक्ष के हल्के विरोध के बावजूद गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक पारित हो गया। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने गोरक्षा आयोग बनाने की सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाया।

सेना में हिमाचल के लिए अलग रेजिमेंट का प्रस्ताव पारित

विधानसभा के शीत सत्र के पांचवें दिन ही हिमाचल के युवाओं के लिए सेना में अलग रेजिमेंट बनाने को प्रस्ताव पारित भी किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने हिमालय रेजिमेंट बनाने का संकल्प सदन में रखा। इसमें सेना में राज्य का कोटा बढ़ाने की भी मांग की गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र से अलग रेजिमेंट की सिफारिश की गई। अब राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी। विधायकों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल की इस मांग को उठाएगा। सत्तर लाख की आबादी वाले प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा युवा देश की सुरक्षा और सेवा के लिए सेना में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल के नाम पर न हो तो हिमालय के नाम पर रेजिमेंट खड़ी की जा सकती है।

धुंध के चलते एक माह बंद रहेगी भुंतर–चंडीगढ़ उड़ान विंटर सीजन को झटका

धुंध में विजिविलिटी कम होने के कारण एक माह तक एयर इंडिया के 72 सीटर हवाई जहाज की भुंतर–चंडीगढ़ उड़ान बंद रहेगी। दिल्ली से भुंतर के बीच उड़ान यथावत रहेगी। एयर इंडिया ने 17 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2019 तक भुंतर– चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवा बंद करने का फैसला लिया है। साल के अंतिम माह में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर पर्यटन कारोबारियों की नजरें टिकी हैं, लेकिन विंटर सीजन में भुंतर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली एकमात्र हवाई सेवा भी बंद हो रही है।

400 डॉक्टरों ने नहीं लिखी पर्ची में जेनेरिक दवाइयां, जारी होंगे नोटिस

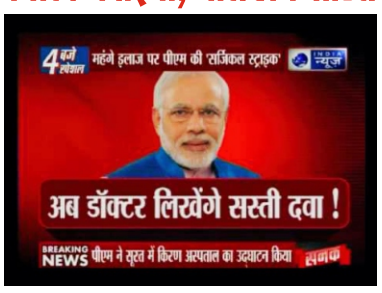

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर जेनेरिक दवाइयां लिखने के निर्देश दिए हैं, बावजूद डॉक्टर इस पर अमल नहीं कर रहे । विभिन्न अस्पतालों से सरकार के पास करीब 400 डॉक्टरों की ऐसी शिकायतें आई हैं, जिन्होंने पर्ची पर यह दवाइयां नहीं लिखी हैं । अब सरकार इन्हें नोटिस जारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य किया है । केवल वही दवाइयां बाहर से लिखी जाएंगी, जो जन औषधि केंद्र में नहीं होंगी ।

शिकायतें आ रही हैं कि केंद्र में दवाइयां होने पर भी डॉक्टर दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं, जो बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं । उन्होंने कहा कि मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं । करीब साढ़े तीन सौ तरह की दवाइयां इन केंद्रों में मौजूद हैं । सरकार जल्द ही और दवाइयों के टेंडर करने जा रही हैं।

सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए कदम उठाने के निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों व विनियमों में सरलीकरण का सुझाव देते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट आश्वासन के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे ।

मुख्यमंत्री ने विभागों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने निर्देश दिए और प्रक्रिया में बदलाव व सरलीकरण के लिए अपेक्षित मामलों को सुझावों सहित मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जन मंच लोगों की शिकायतों का उनके घर–द्वार के समीप समाधान करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है । उन्होंने लोगों में निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं व नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को सरकारी कार्यालयों में आवाजाही में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा और वे अपने मामलों को ऑनलाइन हल करवाने में सक्षम होंगे ।

उन्होंने सभी विभागों को लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आनलाइन सेवाओं का प्रयोग करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को बिलों का भुगतान, राजस्व संबंधी दस्तावेज व अन्य प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्रों को जमा करवाने के लिए आनलाइन सेवाएं लेने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागरिकों की सुविधा के लिए एक छत के नीचे सभी विभागों की ऐप लाने के लिए प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया कि मरीजों के परिचरों की सुविधा के लिए दवा विक्रेताओं को अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए सम्पर्क करना चाहिए। जिला स्तर तक के अस्पतालों में केमिस्टों के दूरभाष नम्बर दर्शाए जाने चाहिए और मरीजों को मेडिकल जांच रिपोर्ट ई–मेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने के लिए विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए।

सभी सरकारी आईटीआई को अपने भवन बनाने के आदेश जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य के सभी सरकारी आईटीआई को अपने भवन बनाने के आदेश दिए गए हैं । वर्तमान में ये आईटीआई किराए के निजी भवनों में चलाई जा रहे हैं। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। जो धन सरकार ने सरकारी आईटीआई के लिए जारी किया है, उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है।

सरकार ने सभी सरकारी आईटीआई को अपने भवन बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इनके नाम जमीन भी कर दी है और भवन बनाने को धनराशि भी मुहैया कर दी थी । इसके बाद भी आईटीआई प्रबंधन ने अपना नया भवन बनाने में खास रुचि नहीं दिखाई । वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब दो दर्जन से अधिक आईटीआई किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं ।

क्या कहते हैं उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री

उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब दो दर्जन सरकारी आईटीआई निजी भवनों में किराया देकर चलाए जा रहे हैं । इनके नाम पर जमीन करने के साथ भवन बनाने को धनराशि भी दी है । आईटीआई प्रबंधन से कहा गया है कि नए भवन बनाने का काम शुरू किया जाए ।

हिमाचल में मानसून सीजन में 1994 करोड़ का नुकसान, सरकार ने प्रस्तुत की रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में मानसून के दौरान हिमाचल में कुल 1994 करोड़ की क्षति की रिपोर्ट अतिरिक्त सूचना सहित अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को सौंप दी है । केंद्र सरकार से इस रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता की संस्तुति के लिए प्रस्तुत किया है। भारी बरसात से बाढ़, भू–स्खलन, बादल फटने और सड़क दुर्घटनाओं में 343 लोगों ने अपनी जानें गंवाईं ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने को शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम को सूचित किया है कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान 1994 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है । लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों की क्षति का प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचा है । इस पर कुल क्षति 881.24 करोड़ रुपए की आंकी गई है ।

कृषि विभाग को 151.98 करोड़, बागवानी विभाग को 441.83 करोड़, कृषि और बागवानी भूमि को 16.03 करोड़ रुपए मत्स्य विभाग को 6.76 करोड़ रुपए आवासीय क्षेत्र के लिए 43.03 करोड़, सामुदायिक परिसंपत्तियों, शहरी विकास को 34.46 करोड़, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य को 430.04 करोड़, राज्य विद्युत बोर्ड को 53.50 करोड़, पशुपालन विभाग को 10 लाख और शिक्षा क्षेत्र को 11.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ।

पब्लिक हेल्थ में पीजी कोर्स शुरु करेगा एचपीयू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

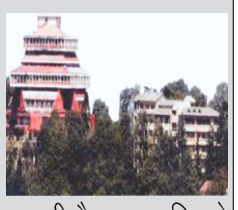

प्रदेश विश्वविद्यालय पीजी सेंटर और विवि से संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2019 से मास्टर इन पब्लिक हेल्थ दो वर्षीय पीजी डिग्री कोर्स शुरू करेगा । विवि यूजीसी के सचिव के आदेशों के बाद कोर्स शुरू किया जाएगा । विवि के कुलसचिव के संबद्ध संस्थानों और कॉलेजों को जारी आदेशों में यह साफ किया गया है । यूजीसी की अधिसूचना यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है । कुलसचिव ने प्राचार्यों से कहा है कि वे समय रहते मास्टर इन पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) कोर्स के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें । इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने करिकुलम तैयार किया है । यह दो साल का होगा ।

DO YOU KNOW...?

Q 1 - Who started the Pajotha movement ?
Answer - Kissan Sabha
Q 2 - When did Kullu came under the dominance of British ?
Answer - 1846 A.D.
Q 3 - Who was the first Governor of Himachal Pradesh ?
Answer - S- Chakravarti
Q 4 - When was Shimla Municipal Committee set-up ?
Answer - 1952
Q 5 - Where is Roerich Art Gallery located in Himachal ?
Answer -Naggar (Kullu)
Q 6 - Where is the Golf Course located in Shimla ?
Answer - Naldehra
Q 7 - Darwar, Bageshwari and Bahar are the types of-----
Answer - Tea
Q 8 - Where is Sobha Singh Art Gallery located ?
Answer - Andreta
Q 9 - What was the earlier name of Advance Studies Institute ?
Answer - Vice Regal Lodge
Q 10 - What are the longitudinal and latitudinal boundaries of Himachal Pradesh ?
Answer - 75°47' East longitude and 30°22' to 33°12' North latitude.

Q 11 - When did Mountaineeing Training Institute at Manali came into existence ?
Answer - 1961
Q 12 - Which glacier was named by Lady Elasheingh about a centurey ago?
Answer - The Lady of Keylong
Q 13 - Which is the highest peak in Himachal Pradesh ?
Answer & Shilla (7025 mts in Kinnaur)
Q 14 - Which river is mentioned as Askini in Vedas ?
Answer - Chenab
Q 15 - Which river is associated with Nathpa Jhakri hydel project ?
Answer - Satluj
Q 16 - Who were the first to inhabit the region of Himachal Pradesh historically ?
Answer - The Kols
Q 17 - Which tribe was the most prominent tribes of early Himachal Pradesh which has a detailed mention in the Mahabharata ?
Answer - Audumbara

Q 18 - Which tribal state is considered as the oldest tribal state of Himachal Pradesh ?
Answer - Kuluta
Q 19 - Name the book which refers to Mihirkula as a powerful king who ruled over both Gandhara and Kashmir ?
Answer - Rajatarangini
Q 20 - When did Mahmud of Ghazni looted the town of Kangra ?
Answer -1019 A.D.
Q 21 - When was Kangra attacked by Mohammad Tughlaq ?
Answer & 1337 A.D.
Q 22 - Who built the new town of Mandi ?
Answer - Ajbar Sen
Q 23 - Who is popularly known as ^Pahari Gandhi* ?
Answer - Baba Kanshi Ram
Q 24 - When did Bilaspur merged with Himachal Pradesh
Answer - 1st July, 1954

प्रसाद योजना में गंगोत्री, यमुनोत्री को शामिल किया गया

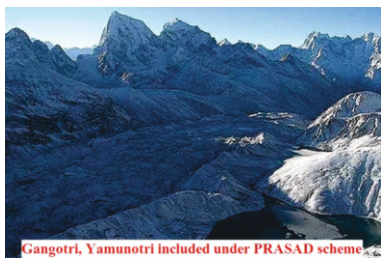

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने देश में तीर्थस्थल और धरोहर स्थल विकसित करने की केंद्रीय योजना के तहत उत्तराखंड में गंगोत्री एवं यमुनोत्री, मध्य प्रदेश में अमरकंटक और झारखंड में पारसनाथ को शामिल किया है। इन नये स्थलों के जुड़ने से 'पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्प्रीचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव' (प्रसाद) यानी 'तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम' योजना में स्थलों की संख्या बढ़कर 25 राज्यों में 41 हो गयी है।

अनुमानित लागत

जानकारी के अनुसार 15 राज्यों में कुल 24 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। इनकी अनुमानित लागत 727.16 करोड़ रुपये है. योजना के आरंभ के बाद से इन परियोजनाओं के लिये कुल 331.15 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्य हेतु 100 प्रतिशत फंडिंग प्रदान की जाती है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सार्वजनिक–निजी साझेदारी (Public–private partnership) तथा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate social responsibility) के तहत भी कार्य किया जा सकता है।

प्रसाद योजना

प्रसाद योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के तहत देश के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। केंद्र सरकार ने 2014–15 में प्रसाद योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास सतत, योजनाबद्ध तथा प्रमुखता से करना है। इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जायेगा। देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है क्योंकि हमारा देश भारत हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन और सूफीवाद जैसे कई धर्मों का देश है। मिशन की रणनीति के हिस्से के रूप में वैसे धार्मिक स्थान जिन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन उत्पादों के तौर पर पेश किया जा सकता है की पहचान की जा रही है और वहां प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के साथ एमओयू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रेल मंत्रालय के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने दिल्ली–एनसीआर के पर्यटकों को दोहरा लाभ उपलब्ध कराने के लिए मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के साथ समझौता किया है। सार्वजनिक–निजी संग्रहालयों के इस समझौते से राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस सम्बंध में रेल मंत्रालय और मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य

समझौते के तहत मैडम तुसाद संग्रहालय जाने वाले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के आगंतुकों को टिकट पर 35 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी।

समझौते के तहत टिकट पर छूट के अलावा स्कूली छात्रों के लिए विशेष प्रावधान है। स्कूली छात्रों को दोनों संग्रहालय जाने पर 45 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे रेल विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और बच्चों को भी राष्ट्रीय नायकों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे छात्रों की सैर अधिक समावेशी, संपूर्ण और मजेदार हो जाएगी।

उद्देश्य:

इस समझौते का उद्देश्य अधिक संग्रहालयों में 3 से 4 दिनों के बीच घुमने के लिए छूट वाली एक टिकट की अवधारणा को बढ़ावा देना है। यह व्यवस्था पर्यटकों के लिए न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ऐसी सुविधा दुनियाभर के महत्वपूर्ण पर्यटन शहरों में पहले से उपलब्ध है।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक संग्रहालय है, जो भारत की रेल धरोहर पर ध्यान आकर्षित करता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 11 एकड़ जमीन में फैला है।

मैडम तुसाद मोम संग्रहालय, दिल्ली

मैडम तुसाद ने वर्ष 2017 में कनॉट पैलेस, नई दिल्ली में अपना 23वां मोम संग्रहालय खोला। यह इस प्रसिद्ध ब्रांड का भारत में पहला मोम संग्रहालय है। कनॉट पैलेस संग्रहालय में महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान जैसी 52 हस्तियों की मोम मूर्तियां हैं. एक वर्ष के अंदर ही यह मोम संग्रहालय दिल्ली का सबसे अधिक लोकप्रिय संग्रहालय बन गया है।

ट्रांसफैट के खिलाफ FSSAI का 'हार्ट अटैक रिवाइंड' अभियान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांसफैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये 'हार्ट अटैक रिवाइंड' नामक अभियान की शुरुआत की है।

हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान अपनी तरह का पहला मीडिया अभियान है जो कि 30 सेकंड की एक सार्वजनिक घोषणा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ट्रांस फैट लेने से हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हर साल विश्वभर में पांच लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

हार्ट अटैक रिवाइंड' अभियान

एफएसएसएआई के अनुसार, हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रांस फैट के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिये निर्धारित वर्ष से एक वर्ष पहले अर्थात् 2022 तक भारत में ट्रांस फैट को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करेगा। 'हार्ट अटैक रिवाइंड' को यूट्यूब, फेसबुक, हॉटस्टार और वूट जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चार सप्ताह की अवधि के लिये 17 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। यह अभियान नागरिकों को ट्रांस फैट के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चेतावनी देता है और स्वस्थ विकल्पों के माध्यम से उनसे बचने के तरीके प्रस्तुत करता है।

ट्रांस फैट क्या होता है?

तरल वनस्पति तेलों को अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य के भंडारण एवं उपयोग अवधि में वृद्धि करने के लिये इन तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इस प्रकार ट्रांस फैट का निर्माण होता है। ट्रांस फैट बड़े पैमाने पर वनस्पति, नकली या कृत्रिम मक्खन, विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं।

ट्रांसफैट के खिलाफ अभियान

स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2023 तक ग्लोबल फूड सप्लाई से आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'REPLACE' नामक पहल को लॉन्च किया है। यह एक छह सूत्रीय कार्यक्रम है।

रक्षा मंत्रालय ने 3,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 3,000 करोड़ रुपये के बराबर की रक्षा खरीद सेवाओं को मंजूरी दी गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस में प्राथमिक हथियार के रूप में रूस में दो भारतीय जहाजों के निर्माण के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों सहित 3000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है।

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के दो स्टेल्थ फ्रिगेट (रडार की नजर में पकड़ नहीं आने वाले युद्धपोतों) के लिये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और सेना के मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' के लिये बख्तरबंद रिकवरी वाहन सहित 3,000 करोड़ रुपये मूल्य की सैन्य खरीद को मंजूरी दी हैं। भारत और रूस की ओर से मिलकर विकसित हो रहे ब्रह्मोस रॉकेट सिस्टम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल सिस्टम माना जाता है।

रूस पर लगे हैं प्रतिबंध

रूस के साथ मिसाइलों की डील को ऐसे समय पर अंजाम दिया गया है जब अमेरिका ने इस देश से होने वाली हथियारों की डील पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने कैटसा कानून के तहत उन सभी देशों और उनके संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है जो रूस से सैन्य सामान खरीदेंगे।

क्षा अधिग्रहण परिषद

भारत में 11 अक्टूबर 2001 को देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी। डीएसी रक्षा खरीद को लेकर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की शीर्ष संस्था है।

केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए 'भाषा संगम' परियोजना आरंभ

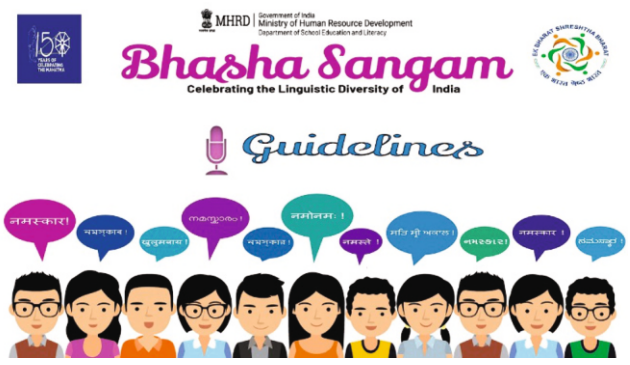

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना के तहत 27 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई।

संगम परियोजना

संगम परियोजना के तहत 28 नवंबर को गुजराती, 29 को हिंदी, 30 नवंबर को कन्नड़, तीन दिसंबर को कश्मीरी, चार को कोंकणी, पांच को मैथिली, छह को मलयालम, सात को मणिपुरी, दस को मराठी, 11 को नेपाली, 12 को उड़िया, 13 को पंजाबी, 14 को संस्कृत का प्रसारण किया गया जबकि , 17 को संथली, 18 को सिंधी, 19 को तमिल, 20 को तेलुगू और 21 दिसंबर को पूरे प्रोजेक्ट का प्रसारण किया गया।

भाषा संगम परियोजना के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा देश के अलग–अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सीखना है।
- छात्र इस परियोजना के तहत हर भाषा के पांच वाक्य सीखेंगे। इसके बाद उन्हें प्रार्थना के समय इन वाक्यों को बोलना होगा।
- छात्रों को घर पर अभिभावकों के साथ इन वाक्यों पर विचार–विमर्श करना होगा। स्कूलों में प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी का वीडियो बनेगा तथा यह वीडियो सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
- भाषा संगम प्रॉजेक्ट के तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा रहा है।
- इसमें हिन्दी, असमिया, बंगाली, बोडो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, डोगरी भाषा छात्रों को बोलनी सिखाई जा रही है।

संविधान की आठवी अनुसूची

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। वर्ष 1967 में, सिन्धी भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। हाल में 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए गए।

भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण के लिए 'डिजिटल स्काई' पोर्टल शुरु

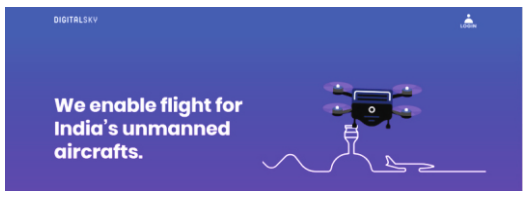

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'डिजिटल स्काई' की शुरुआत की है, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विदित हो कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में ड्रोन उड़ाने के लिए नियम एवं शर्तें तय किये थे। ये नियम एक दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा।

ड्रोन की पांच श्रेणियां

मंत्रालय की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो, माइक्रो, स्माल, मीडियम और लार्ज।

नो ड्रोन ज़ोन

मंत्रालय ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है. एयरपोर्ट्स के आसपास, इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, मिलिट्री इंस्टालेशंस तथा अन्य कूटनीतिक लोकेशन।

ट्रेन -18 ने सफलतापूर्वक 180 किमी/घंटा की रफ़्तार पर ट्रायल रन पूरा किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय रेलवे की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन–18 परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड से सफलतापूर्वक दौड़ी। इस प्रकार यह देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 220 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे पहले भारतीय पटरियों पर टैल्गो ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ी थी, लेकिन वह स्पेन की ट्रेन थी। मौजूदा समय में भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर करती है।

परीक्षण के बारे में जानकारी

भारत की नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेन कही जा रही ट्रेन–18 का ट्रायल दिल्ली–मुंबई राजधानी रूट पर किया जा रहा है। यह ट्रेन पहले ट्रायल के दौरान 170 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ी, जबकि दूसरे ट्रायल में इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया।

ट्रेन–18 की विशेषताएं

- चेन्नई के इंटिग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे तैयार किया है और साल 2018 में बनने के कारण इसे ट्रेन–18 नाम दिया गया है।
- इस ट्रेन की पूरी बॉडी ख़ास एल्यूमिनियम की बनी है यानी यह ट्रेन वज़न में हल्की भी होगी।
- इसे तुरंत ही ब्रेक लगाकर रोकना आसान है और इसके तुरंत ही तेज़ गति भी दी जा सकती है।
- इस ट्रेन के मध्य में दो एक्जिक्यूटिव कंपार्टमेंट होंगे। प्रत्येक में 52 सीटें होंगी. वहीं सामान्य कोच में 78 सीटें होंगी।
- शताब्दी की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है जबकि यह 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकेगी।
- ट्रेन–18 में जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली के अलावा अलहदा तरह की लाइट, ऑटोमेटिक दरवाजे और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक: आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

इतिहास रचने वाले दिव्यांग, आप भी जाने इनकी प्रेरक कहानी

इनके जज़्बे को दुनिया करती है सलाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुछ करने के लिए इंसान की शारीरिक क्षमता की नहीं बल्कि इंसान के अंदर मजबूत इरादे की जरूरत होती है। इस अंक में दुनिया को ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो मजबूत इरादे की मिसाल हैं। उनमें से कुछ किसी दुर्घटना में तो कोई किसी और वजह से दिव्यांग हुए। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ हटकर ऐसा किया कि इतिहास में नाम दर्ज हो गया।

मेजर देवेंद्र पाल

भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर देवेंद्र पाल सिंह लोगों के लिए प्रेरणा हैं। करगिल युद्ध के दौरान अपना दायां पैर गंवाने वाले पाल ने अपनी दिव्यांगता को ही अपनी ताकत बनाई। अपने कभी हार नहीं मानने वाले ज्ज़बे के कारण वह भारत के पहले ब्लेड रनर बन गए। उन्होंने 9 मैराथन में हिस्सा लिया। तीन हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के बाद सेना ने उनकी मदद की और उनको आयरलैंड में बना कृत्रिम पैर उपलब्ध कराया ।

कार्तिक साहनी

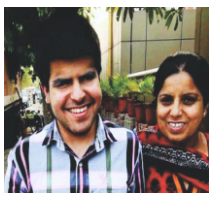

जब 18 साल के कार्तिक साहनी ने 12वीं में 96 फीसदी नंबर हासिल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इतना नंबर लाने वाले पहले दृष्टिबाधित छात्र बन गए। दृष्टिबाधित होने के कारण लगातार तीन सालों तक उनको आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। अंत में उनकी कोशिश रंग लाई और बनाया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में उड़न परी पी.टी.उषा के रेकॉर्ड को तोड़ दिया। इतना ही नहीं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा पदक हासिल करने का रेकॉर्ड उनके नाम है।

अरुणिमा सिन्हा

अरुणिमा एक हादसे में बायां पैर खो चुकी हैं और दाएं पैर में लोहे की रॉड पड़ी है। उनके पैर खोने की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा को लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त कुछ लुटेरों ने चेन छीनने की कोशिश में ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, इस हादसे के बाद वह उन्होंने अपने पैर खो दिए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं।

सुभरीत कौर घुम्मन

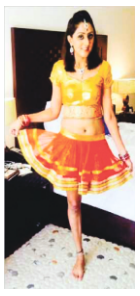

सुभरीत कौर एक पैर की डांसर के रूप में लोकप्रिय हैं। एक दुर्घटना में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा। पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली सुभरीत ने दुर्घटना के बाद हौसला नहीं हारा। एक डांस रिऐलिटी शो में चुने जाने के बाद वह चर्चा में आईं।

नवीन गुलिया

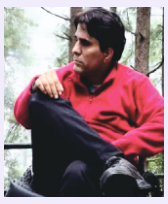

दिल्ली के रहने वाले नवीन गुलिया सेना में कमांडर के तौर पर शामिल होना चाहते थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक स्पोर्ट्स दुर्घटना में गुलिया लकवाग्रस्त हो गए और उनकी बाईं स्पाइन बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ऐसा किया कि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया। वह पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने दिल्ली से मार्सेमिक ला का सफर किया। मार्सेमिक ला 8,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है।

शरत गायकवाड

एक हाथ से मजबूर शरत ने 9 साल की उम्र से ही तैरने का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उन्होंने पैरा इंचियोन एशियन गेम्स 2014 में 6 पदक जीतकर इतिहास बनाया। इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में उड़न परी पी.टी.उषा के रेकॉर्ड को तोड़ दिया। इतना ही नहीं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा पदक हासिल करने का रेकॉर्ड उनके नाम है।

एच.बोनीफेस प्रभु

चार साल की उम्र में प्रभु को लकवा मार दिया था । उन्होंने इसे अपने जीवन के लक्ष्यों पर हावी नहीं होने दिया और रेग्युलर स्कूल में पढ़ाई जारी रखी । कठिन परिश्रम और समर्पण की बदौलत वह वह दुनिया के मशहूर वीलचेयर टेनिस प्लेयर बने । 1998 वर्ल्ड चौंपियनशिप में उन्होंने पदक जीता । 2014 में भारत सरकार ने उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया ।

साई प्रसाद विश्वनाथन

बचपन में उनके शरीर का निचला आधा हिस्सा बेकार हो गया था और काम करना बंद कर दिया था । लेकिन उन्होंने अपनी सफलता के रास्ते में उसे बाधा नहीं बनने दिया । वह भारत के पहले स्काईडाइवर बने । वह पहले दिव्यांग भारतीय हैं जिन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्काईडाइविंग करके लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में अपना नाम दर्जा कराया । मौजूदा समय में वह भारत में डेलॉइट यूएस के रिस्क कंसल्टेंट हैं । उन्होंने सहस्र नाम के संगठन की भी स्थापना की है । यह संगठन वित्तीय रूप से वंचित उन छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराता है जिनके अंदर कुछ करने की संभावना है।

पद्म श्री डॉ.मलाथी कृष्णामूर्ति हॉला

एक साल की उम्र में वह पोलियो का शिकार हो गई थीं। काफी इलाज हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हल्का सा फर्क यह आयाथा कि शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़ी ताकत आ गई थी बाकी शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक असहाय बच्चे से पदम श्री विजेता बनने तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक है। 300 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें पदमश्री व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने दक्षिण कोरिया, बार्सिलोना, एथेंस और बीजिंग में आयोजित पैरालिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बीजिंग, बैंकाक, दक्षिण कोरिया और कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई खेलों में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विश्व मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों और बेल्जियम, कुआलालंपुर और इंग्लैंड में ओपन चौंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

साधना ढांड

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पेंटर साधना को हड्डी से संबंधित रोग है। वह श्रवण शक्ति से भी वंचित हैं । लेकिन उन्होंने इन बाधाओं पर बिजय पाते हुए पेंटिंग और फोटोग्राफी के अपने शौक को आगे बढ़ाया । वह दिव्यांग बच्चों के लिए संगठन भी चलाती हैं ।

गिरीश शर्मा

गिरीश शर्मा एक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जब वह 2 ही साल के थे तो एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। उन्होंने जर्मनी, इस्राइल और थाइलैंड में बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया । उन्होंने पैरालिंपिक एशिया कैप में एक गोल्ड मेडल भी जीता ।

भरत कुमार

वह सिर्फ दायें हाथों के साथ ही पैदा हुए थे । लेकिन यह उनके सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बनी । 10 दिसंबर, 1989 को जन्मे भरत कुमार ने पैरा स्विमिंग प्रतियोगिताओं में 50 से ज्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल वॉटर कंपनियों को बंद करने की चेतावनी दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि यदि बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियों ने पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया तो इन कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा है कि कुछ संयंत्रों के पास पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ या प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं।

एक खबर के अनुसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार, न्यायमूर्ति एजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति फैसल अरबाब की पीठ ने बोतलबंद पानी के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए जल आयोग की ओर से दायर रिपोर्ट पर निराशा व्यक्त की है । रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि कुछ कंपनियों के पास पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षत कर्मचारी नहीं हैं, वहीं कुछ अन्य संयंत्रों के पास पर्यावरण संबंधी जरूरी मंजूरी नहीं हैं ।

चीफ जस्टिस ने कहा, 'आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, मैं बोतलबंद पानी की कंपनियों पर ताला लगा देना चाहता हूं । जो कंपनियां पानी चुरा रही हैं उन्हें मुआवजा देना होगा।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कंपनियों ने अपने कामकाज में सुधार नहीं किया तो शीर्ष अदालत के पास उन्हें बंद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा । उन्होंने कहा, 'यदि इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए तो कोई प्यास से नहीं मरेगा ।'

G-20: आतंकवाद से व्यापार तक, देशों के प्रमुखों के साथ मोदी ने की यह बात

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जी–20 समिट के इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में पीएम मोदी ने संयुक्त रूप से वैश्विक समस्या बन चुके आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने शनिवार को कहा कि यूरोपियन कमिशन के प्रेसिडेंट जीन क्लाउड जंकर, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क और जर्मन चांसलर ऐंगला मर्केल के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे देश संयुक्त रूप से आंतक के ख़िलाफ एक–दूसरे का साथ दे सकते हैं ।

इसके अलावा पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण नियमों के अनुरूप भारतीय कंपनियों को भी डेटा पर्याप्तता का स्टेटस दिया जाएगा । यूरोपियन यूनियन का नया नियम हाल ही में लागू हुआ है ।

यूरोपियन कमिशन के प्रेसिडेंट जीन क्लाउड जंकर और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी ने ट्रेड और फ्री ट्रेड नेगोसिएशन पर भी चर्चा की । गोखले ने बताया, 'उन्होंने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि भारत इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके संतुलित नतीजे आने चाहिए, जो भारतीय उद्योग और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हों ।

पीओके को भारत का हिस्सा दिखा चीन ने पाकिस्तान से नाराजगी के दिए संकेत

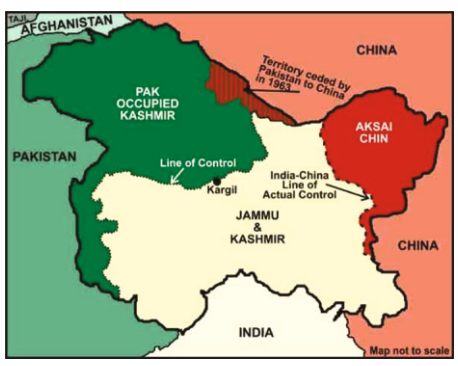

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने भले ही पाकिस्तान में भारी–भरकम निवेश कर रखा हो पर इस समय वह उससे काफी नाराज़ है । हाल में चीन के सरकारी टीवी नेटवर्क (CGTN) पर दिखाए गए मैप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया था । इसे पाकिस्तान के प्रति चीन की गहरी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है । चीन ने यह रुख ऐसे समय में दिखाया है जब 10 दिसंबर को भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास होना है और करतारपुर मसले पर डिबेट भी हो रही है ।

दरअसल, CGTN ने कराची में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले की रिपोर्टिंग के दौरान PoK को भारत का हिस्सा दिखाया । इसे पेइचिंग के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि चीन अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान से काफी नाराज है । सूत्रों का कहना है कि CGTN ने मैप के लिए फिक्स्ड टेंपलेट्स का इस्तेमाल किया और प्रॉडक्शन स्टाफ को इसमें हेरफेर करने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों की मानें तो टेंपलेट को लेकर फैसला उच्च अधिकारियों के निर्देश के बगैर आम प्रॉडक्शन स्टाफ ने नहीं लिया होगा ।

आपको बता दें कि चीनी प्रशासन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर नीतियों में परिवर्तन से पहले आधिकारिक मीडिया का इस्तेमाल टेस्ट बैलून के तौर पर करता रहा है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ एक केस में अपने रुख से अलग चलने के कारण चीन के आधिकारिक नीति बदलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

गौर करने वाली बात यह है कि आधिकारिक तौर पर जारी किए गए मैप में चीन ने कभी भी च्वज्ञ को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। सूत्रों का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर से मिले सिग्नल के बगैर सरकारी मीडिया अलग मैप का इस्तेमाल भी नहीं करता है। आपको बता दें कि मैप चीन में संवेदनशील मामला है इसलिए किताबों और पत्रिकाओं में पेइचिंग के आधिकारिक नजरिए से अलग नक्शे को जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाता है।

अमेरिका अगर प्रतिबंधित मिसाइलें बनायेगा तो रुस भी ऐसा ही करेगा: पुतिन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका प्रतिबंधित मिसाइलों को विकसित करता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा । पुतिन ने कहा कि अमेरिका यदि एक महत्वपूर्ण हथियार संधि से बाहर निकलता है और उसके द्वारा प्रतिबंधित मिसाइलों को विकसित करना शुरू करता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा ।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने नाटो की एक बैठक में घोषणा की थी कि अमेरिका रूसी 'धोखाधड़ी' के कारण 60 दिनों में इंटरमीडिएट–रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी (आईएनएफ) के तहत अपने दायित्वों को छोड़ेगा । पोंपियो के बयान के एक दिन बाद पुतिन का बयान आया है । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरूआत में आईएनएफ से अलग होने के अपने निर्णय की घोषणा की थी।

पुतिन ने टेलीविजन पर दिए अपने बयान में कहा,'ऐसा लगता है कि हमारे अमेरिकी सहयोगियों का मानना है कि स्थिति इतनी बदल गई है कि अमेरिका के पास इस प्रकार के हथियार होने चाहिए।' उन्होंने कहा,'हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक बहुत ही सरल, उस मामले में हम भी वही करेंगे।'

विधानसभा चुनाव परिणाम : ये रहे पांचों राज्यों के नतीजे

जानिए कहां – किस पार्टी को मिली कितनी सीटें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत सभी पांचों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान छीन लिया है। इसमें छत्तीसगढ़ को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती हैं। हालांकि यहां कांग्रेस बहुमत से बस दो कदम दूर रह गई।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे

मध्यप्रदेश में मतदाताओं ने पहली बार खंडित जनादेश दिया है। कांटे के मुकाबले में फंसी दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 114 सीटों के साथ पहले नंबर पर और 109 सीटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर है। वहीं, बसपा को 2, सपा को 1 और 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। 230 विधानसभा सीटों वाली राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे

राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी बरकरार रही। यहां भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस नई सरकार बनाने को तैयार है। यहां कांग्रेस के पक्ष में जिस तरह एकतरफा मुकाबला बताया जा रहा था, वैसा नहीं रहा। जैसे–जैसे मतगणना आगे बढ़ी, कांटे की टक्कर साफ दिखाई देने लगी। अंततः वहां कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिल गई। कुल 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए 99 सीटों का आंकड़ा छू लिया। वहीं, सूबे में भाजपा को 73 सीटें ही मिल सकीं। हालांकि राज्य में दोनों दलों के दिग्गजों ने अपनी–अपनी सीटें जीत लीं। दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से मानवेंद्र सिंह को हरा दिया। वहीं कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सी पी जोशी ने अपनी–अपनी सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस की दिग्गज नेता गिरिजा व्यास को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राज्य में कई मौजूदा मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि राज्य में वर्ष 1993 के बाद कोई भी दल लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाया है। तब भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। इसके बाद 1998 व 2008 में कांग्रेस तो 2003 व 2013 में भाजपा सत्ता में रही।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे

छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफी समेत फसलों के उचित मूल्य के कांग्रेस के वादे का दांव सफल रहा। यहां भाजपा को राज्य की 90 में से 15 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस पहली बार दो तिहाई बहुमत से जीती। कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ जीत का विजय पताका फहराया। इसी के साथ कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत ने 15 साल से चल रहे रमन सिंह के शासन का अंत कर दिया है। वहीं, बीएसपी को 2 और जनता कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में मतदाताओं का गुस्सा इस कदर था कि रमन सिंह सरकार के पांच मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, महेश गगडा, दयालदास बघेल और अमर अग्रवाल चुनाव हार गए। राज्य में भाजपा की बड़ी हार का कारण अजित जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी रही।

तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे

तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर का जादू मतदाताओं के सिर चढ़ कर बोला। राज्य की 119 में से 88 सीटों पर कब्जा कर सत्तारूढ़ टीआरएस ने सूबे में कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस–तेलुगू देशम पार्टी गठबंधन को महज 22 सीटें मिली, जबकि भाजपा को एक ही सीट मिल पाई। इसके अलावा मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को छह सीटें मिलीं। राज्य में जल्द चुनाव कराने के लिए केसीआर सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया था। हालांकि उनका यह दांव बेहद सफल साबित हुआ।

मिजोरम चुनाव

मिजोरम चुनाव सिर्फ तीन वोट के अंतर से भी हुआ हार–जीत का फैसला हुआ। मिजोरम विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कांग्रेस महज पांच सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। एमएनएफ को 26 सीटें मिली और जोराम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम को आठ सीटें मिली। बीजेपी ने भी आठ फीसदी वोट पाकर एक सीट के साथ राज्य में अपना खाता खोला।

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग–अलग राय व्यक्त की। तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे। जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। छन्नू लाल वर्मा को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे।

भारत में मौत की सज़ा

भारत में मौत की सज़ा कुछ गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 के बाद 5 घटनाओं में मौत की सज़ा दी है। भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है। अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है। यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल वर्ष 1953 से वर्ष 1963 के दशक में ही यह संख्या 1422 है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक नीचली अदालतों द्वारा कुल 1617 कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार वर्ष 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है।

दिसम्बर 2007 में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था। इसके बाद नवम्बर 2012 में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।

यौन उत्पीड़न पोर्टल 'शी–बॉक्स' को केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों और जिलों से लिंक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'शी–बॉक्स' को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है। 'शी–बॉक्स' पर दर्ज कराई गई शिकायत के प्रत्येक मामले तत्काल निपटारे के लिए संबंधित केंद्र/राज्य अधिकारियों के पास सीधे चले जाएंगे और वे अपने अधिकार क्षेत्र में मामले के संबंध में कार्रवाई करेंगे। 'शी–बॉक्स' की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी।

उद्देश्य

'शी–बॉक्स' पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को तेजी से राहत उपलब्ध कराने का एक प्रयास है. इस पोर्टल के केंद्र/राज्य सरकारों से लिंक होने के कारण एक बार इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर सीधे ही संबंधित नियोक्ता के अनुभाग में भेज दी जाएगी. इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ–साथ शिकायतकर्ता भी पूछताछ में हुई प्रगति की निगरानी कर सकता है।

क्या है 'शी–बॉक्स'

'शी–बॉक्स' की शुरूआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी महिला कर्मियों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन महिलाओं ने पहले ही यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को अपनी लिखित शिकायतें भेजी हैं वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

सामान्य ज्ञान

पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
उत्तर–चन्द्रमा
'गाँधी' फ़िल्म में गाँधी की भूमिका किसने निभाई ?
उत्तर – बेन किंग्सले
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर – 5 सितंबर
जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था?
उत्तर – 1945 में
भांखड़ा नांगल बाँध किस नदी पर है?
उत्तर –सतलुज
भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है?
उत्तर –कमल
धनराज पिल्लै किस खेल से सम्बंधित है?
उत्तर –हॉकी
सयुंक्त राष्ट्र संघ U-N-O- की सुरक्षा परिषद् में कितने स्थाई सदस्य है ?
उत्तर – 5
कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है ?
उत्तर –हड़प्पा
चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था?
उत्तर – मराठो द्वारा
'भूदान आंदोलन' किसने शुरू किया किया था?
उत्तर –विनोभा भावे
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी?
उत्तर –लार्ड मैकाले
'फ़्लाइंग सिख' के नाम से किसे जाना जाता है?
उत्तर –मिल्खा सिंह
नींबू और सन्तरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
उत्तर – विटामिन सी
उदय शंकर किससे सम्बंधित है?
उत्तर – नृत्य
संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे?
उत्तर – डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर
त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है?
उत्तर– जिला परिषद
लक्षदीप की राजधानी है।
उत्तर – कवरती
श्री लंका की मुद्रा का नाम है।
उत्तर–रुपया
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
उत्तर – जवाहर लाल नेहरू
'गुरुत्वाकर्षण' की खोज किसने की थी?
उत्तर – न्यूटन
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है।
उत्तर –रविन्द्र नाथ टेगोर
द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे सम्बंधित है?
उत्तर – श्रेष्ठ गुरु / प्रशिक्षक
खजुराहो स्थित है–
उत्तर –मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है।
उत्तर – देहरादून
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
उत्तर–स्वामी विवेकानंद
भारतीय मानक समय आधारित है।
उत्तर –82° 30′ पूर्व देशान्तर पर
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है?
उत्तर –अरुणाचल प्रदेश
कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है?
उत्तर – चीन
पृथ्वी के नजदीक वायुमण्डल की सबसे निचली परत है–
उत्तर – क्षोभ मण्डल
भारतीय सेना में 'विजयंत' नाम है–
उत्तर – एक टैंक का
चीनी यात्री फाह्यान किसके काल में भारत आया था?
उत्तर –विक्रमादित्य
भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है।
उत्तर–असम
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है
उत्तर–पश्चिम बंगाल
भारत के किस शहर में जंतर–मंतर स्थित है?
उत्तर–दिल्ली
भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है?
उत्तर – पश्चिम बंगाल
तेलगु किस राज्य की राजभाषा है?
उत्तर – आंध्रप्रदेश
हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते है–
उत्तर –11
बांग्लादेश की मुद्रा है
उत्तर–टका
नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था?
उत्तर –मिस्त्र सभ्यता
किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था?
उत्तर – गया
प्रसिद्ध नाटक 'शकुंतला' किसने लिखी थी?
उत्तर –महाकवि कालिदास
ज्वार सबसे ऊँचा कब होता है–
उत्तर – जब सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते है
कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नही है?
उत्तर –मध्य प्रदेश
खैबर दर्रा स्थित है–
उत्तर –अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच
कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नही निकलती है
उत्तर–यमुना
कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है
उत्तर –कानपुर
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है–
उत्तर – भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) जोड़ते हैं
उत्तर–व्यापार केन्द्रो और राज्य की राजधानियों को।
कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर –नासिक
कोयना बांध स्थित है–
उत्तर – महाराष्ट्र
खरीफ की फसल काटी जाती है–
उत्तर –नवम्बर के प्रारम्भ में
हिमानी (ग्लेशियर) बर्फ का एक विशाल पिंड है, जो–
उत्तर – हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलो पर छाया रहता है
कौन सी कायांतरित शैल है?
उत्तर – संगमरमर

सौभाग्य योजना

देश में एक ओर बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर यह भी बड़ी हकीकत है कि आजादी के सात दशकों बाद भी भी करीब चार करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भी इस सूची में शामिल है जहां कुछ गांवों के लोग आज भी लालटेन के मधम उजाले से अपने जीवन को रोशन करते हैं। बच्चे पढ़ाई भी मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी में करते हैं तो महिलाएं भी बिना बिजली के पेरशानी झेलने को मजबूर रहती है।

शायद ग्रामीण भारत की इसी सबसे बड़ी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरूआत की। उम्मीद है कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं के जीवन को ना सिर्फ धुएँ से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की बल्कि उनका जीवन भी आसान बनाया उसी प्रकार सौभाग्य योजना भी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में कामयाब रहेगी। आइए जानते हैं सौभाग्य योजना क्या है और इसका लाभ किसको और कैसे मिलेगा।

क्या है सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित की गयी इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। जिन लोगों का नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बिजली का कनेक्शन मात्र 500 रुपए देकर मिल सकता है और यह 500 रुपए भी वह दस आसान किस्तों में दे सकते हैं। जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां इस योजना के तहत सरकार की ओर से हर घर को एक सोलर पैक दिया जाता है जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा है। बिजली से वंचित चार करोड़ घरों की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना के लिए 16 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है।

इस योजना के तहत सरकार मिट्टी के तेल का विकल्प भी बिजली को बनाएगी। इसके लिए सरकारी कंपनी ओएनजीसी की ओर से नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए अच्छा खासा फंड रखा गया है। सरकार चाहती है कि युवा घरेलू काम में आने वाले और कम ऊर्जा खपत वाले बिजली के उपकरण बनाएं। इस योजना की अन्य मुख्य बातों में शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा और संचार के साधन को और बेहतर बनाना तथा मुख्य रूप से रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है।

सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिये लोगों को खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा क्योंकि जब घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंद होकर रह जाती हैं। इस योजना के अनुसार बिजली की उपलब्धता को पूरा करने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ए के भल्ला के अनुसार केंद्र देश के हर घर में बिजली को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। देश भर में लगभग 73.38 प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन है।

योजना का नाम – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

किसके द्वारा घोषित की गयी– केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना की अवधि : 31 मार्च 1019

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16, 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें बजटीय सहायता 12, 320 करोड़ रुपए है। जहां बिजली नहीं जा सकती वहां

'सौलर पैक' दिया जा रहा है। 5 एलईडी लाइटें, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग और पांच वर्ष तक इसकी मुरम्मत का खर्च सरकार की ओर से प्रावधान है। बिजली कनेक्शन के लिए हर गांव में कैंप लगाया जाता है। योजना से गांव में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और गरीब 10 किश्तों में भी पैसे दे सकते हैं। बिजली बिल के लिए स्मार्ट और पेड मीटर लगाया जाता है। योजना के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

ये हो रहे फायदे

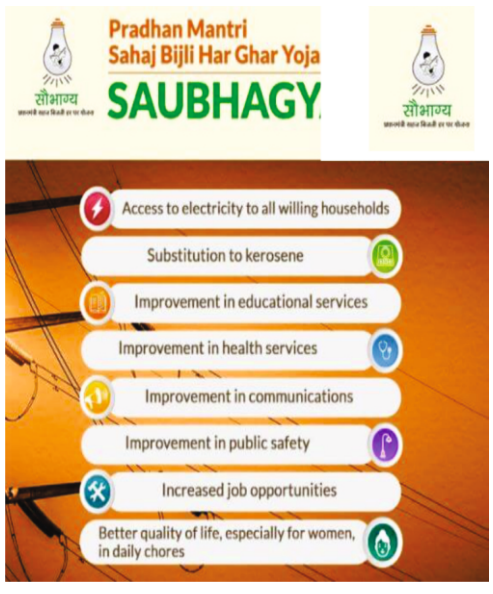

योजना से पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। बिजली उपलब्ध होने से लोग ईंधन का उपयोग कम करते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में मोबाइल, रेडियो और टेलविजिन के माध्यम से केनेक्टीविटी बढ़ेगी। आर्थिक गतविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही महिलाएं होगी और विशेष रुप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। योजना से जुड़ने के लिए मोबाइल एप्प का इस्तेमाल किया जाता है और इसी एप्प के जरिए आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं।

योजना का शुभारंभ

इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने लांच किया है। इस स्कीम की घोषणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर की गयी है। इस स्कीम के तहत सरकार गांवों के साथ–साथ सभी शहरी इलाकों में भी बिजली पहुंचाएगी। इस स्कीम को सही तरह से चलाने की जिम्मेवारी ग्रामीण विद्युत निगम को दी गयी है और ये निगम इस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर कार्य कर रहा है।

योजना से जुड़े दस्तावेज

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नीचे बताये गए दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी, इसलिए इन सब को रखना अनिवार्य है :

आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, मोबाइल नंबर बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस।

सौभाग्य योजना का कुल बजट

इस योजना के लिए सरकार ने 16, 320 करोड़ रुपये का कुल बजट रखा है। सरकार ने सौभाग्य योजना में 12,320 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता का भी प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14,025 करोड़ रुपये 2. 50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए।

सौभाग्य योजना के तहत चयनित इलाके की सूची:

बिहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्य

सौभाग्य योजना का उद्देश्य

शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा और संचार के साधन को और बेहतर बनाना है। मुख्य रूप से सरकार सौभाग्य योजना के जरिये सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। सौभाग्य योजना से लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। अंधेरे में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, खास तौर पर महिलाएं अंधेरे में घर से निकलना नहीं चाहती। सरकार खुद गरीब परिवार के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब लोगों को मुखिया और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। सरकार ने 31 मार्च 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सरकारी कंपनियों का योगदान

सरकारी कंपनी ओएनजीसी की ओर से इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए भी बड़ा फंड रखा गया है। सरकार चाहती है कि युवा घरेलू काम में आने वाले और कम ऊर्जा खपत वाले बिजली के उपकरण बनाने की पहल करें।

योजना से जुड़ा वेब पोर्टल

स्कीम पर निगरानी रखने के लिए, इस स्कीम की प्रोग्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए और स्कीम के लिए खुद का रजस्ट्रेशन करवाने के लिए एक वेब पोर्टल http://saubhagya-gov-in/ भी बनाया गया है। इस पोर्टल को 16 नवंबर 2017 को लांच किया गया था। इस वेब पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपना नाम पंजीकरण करवा

सकता है। इतना ही नहीं समय समय पर इस वेब पोर्टल पर जाकर ये भी जानकारी प्राप्त कर सकता हैं कि उसको कब तक बिजली दी जाएगी। योजना से जुड़ी मोबाइल एप्प वेब पोर्टल पेज के अलावा इस स्कीम से जुड़ी एक मोबाइल एप्प भी हैं। जिसके जरिए भी लोग इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

मोबाइल एप्प के जरिए कैसे करें पंजीकरण

इस स्कीम के लिए अगर आप मोबाइल एप्प के जरिए अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कीम से जुड़ी एप्प को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। अब उस एप्प में दिए गए एक फार्म को भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रीसिटी कनेक्शन लेने के लिए हो जाएगा।

हासिल किया गया लक्ष्य

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर स्कीम की तय सीमा अगले साल तक खत्म होने वाली है और इस समय तक सरकार ने 60 लाख से अधिक घरों को एलेक्ट्रीफाएड कर दिया है। जबकि 3,20,45,929 घरों को एलेक्ट्रिएड किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

8 राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया

केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह की ओर से जारी बयान के मुताबिक सौभाग्य योजना के अंतर्गत 8 राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया हैं। इसके साथ, देश में अब कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है। ये आठ राज्य मध्यप्रदेश ,त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये।

पूर्ण विद्युतीकरण से वंचित

महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और उम्मीद है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा। विद्युतीकरण की वर्तमान गति के मुताबिक देश के सभी 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा हो जायेगा।

सौभाग्य योजना के तहत पुरस्कार योजना:

विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों / राज्य के विद्युत विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 300 करोड़ रूपये की पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां / विद्युत विभाग को कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। पुरस्कार के उद्देश्य से राज्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार तीन श्रेणियों में

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF POWER

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे। यह श्रेणियां हैं:

- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अलावा अन्य राज्यों (बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं।
- 31 दिसम्बर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का काम करने वाले राज्यों को सौभाग्य के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरु किया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

- Launched by Hon'ble PM on 11 October 2014
- Hon'ble Members of Parliament are guiding the Gram Panchayats towards holistic Development
- SAGY GPs are the schools of local level development and governance
- Inspiration to neighbouring Gram Panchayats to learn and adapt
- Convergence of Central/ Centrally sponsored schemes/ State Schemes and partnership with private, voluntary and cooperative sectors

- इस योजना के लिए महात्मा गाँधी के सिद्धांतों और मूल्यों पर ज्यादा भार दिया गया है। इस योजना के तहत गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन बसाए जाएंगे जिससे गाँव का डेवलपमेंट हो पाए।
- इस योजना के तहत हमारे देश के गाँवों के क्षेत्रों में जैसे की खेती, स्वास्थ्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, रोजी–रोटी आदि में सुधार लाया जाएगा।

Sansad Adarsh Gram Yojana के तहत गाँव के लोगों के जीवन में नए सुधार आयेंगे इस वजह से उन्हें नयी तकनीक और सुविधाएं प्राप्त होंगी जिससे वह और तरक्की कर पाएंगे। यह योजना बेहद ही अद्वितीय और लचीली भी है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और इतना ही नहीं वह कुछ सेवाओं का मूल्य बढ़ाना चाहते थे, जैसे की अन्त्योदय, लड़कों और लडकियों में समानता, महिलाओं की गरिमा बनाये रखना, स्वच्छता आदि गांव के लोगों में और गाँव में आने वाला परिवर्तन सबके लिए मिसाल होना चाहिए।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2019 तक देश के तीन गाँवों को आदर्श ग्राम बनाने का था जो की 2016 में खत्म हो गया था। इसके बाद 5 गाँवों को 2024 तक आदर्श गाँव बनाने का भी उद्देश्य है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हेतु मौजूदा योजना और नयी योजनाओं को प्रक्षेपित कर ग्राम को बढ़ावा देकर गाँव के लोगों को अच्छा जीवन निर्वाह कर पाएंगे और पुरे गाँव का विकास करवाने होंगे
- गाँव के लोगों में गुणवत्ता, सभी के जीवन स्तर के लिए उनकी बुनियादी सेवाओं में सुधार लाना चाहिए, उत्पादकता में बढौतरी, मानव विकास, बेहतर आजीविका के लिए प्रयास, असमानताओं को कम करके अपने अधिकारों को जान सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे
- इस योजना के तहत एक आदर्श गाँव बनाया जाएगा जो की सबके लिए एक मॉडल प्रदान करे, जिससे पड़ोसी ग्राम भी इससे प्रभावित हो और उस ग्राम के जैसा विकास करे।
- इस योजना के तहत उस आदर्श ग्राम को एक स्कूल के तौर पर लिया जाएगा और दुसरे गाँव भी इससे प्रभावित होकर विकास कर पाएंगे।

SAGY के तहत आदर्श गांव के लिए गांव कैसे चुना जायेगा?

इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ शर्तों के आधार पर आदर्श ग्राम के लिए चुना जाएगा :

- कोई भी समतल विस्तार की ग्राम पंचायत में जन संख्या 3000 से 5000 और पहाड़ी विस्तारों में 1000 से 3000 होनी चाहिए।
- संसद के सदस्य कोई भी अनुरूप ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने के लिए और आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुन सकता है। वह सदस्य अपना खुद का गाँव या फिर अपने पत्नी–पति का गाँव भी आदर्श ग्राम बनाने के लिए पसंद कर सकता है।
- संसद सदस्य कुल 3 गाँव आदर्श ग्राम बनाने के लिए पसंद कर सकता है।
- इतना ही नहीं इस योजना के तहत लोकसभा के सदस्य भी अपने मत विस्तार मे से कोई गाँव आदर्श गाँव बनाने के लिए पसंद कर सकता है। सिर्फ लोकसभा का सदस्य ही नहीं पर इस योजना के तहत राज्यसभा के सदस्य भी अपने मतविस्तार के किसी गाँव को आदर्श गाँव के लिए पसंद कर सकते है।
- कुछ राज्यसभा के सदस्य जिनको किसी सेक्टर के मंत्री पद पर नामांकित हो, वह अपने मतविस्तार से आदर्श ग्राम बनाने के लिए कोई भी गाँव को पसंद कर सकते है।
- अगर कोई ग्राम पंचायत किसी सदस्य के रहते आदर्श ग्राम के लिए चयनित की गयी हो और उस सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाए तो वह ग्राम पंचायत को Sansad Adarsh Gram Yojana के तहत आदर्श गाँव बनाएगा।
- नया सदस्य भी इस योजना के तहत अपने मतविस्तार से कोई गाँव आदर्श गाँव के लिए पसंद कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस अब गांवों को भी स्मार्ट बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में हुए बड़े समारोह में आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2019 तक सभी सांसद अपने क्षेत्र के 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाएंगे। 2016 तक एक गांव को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य था।

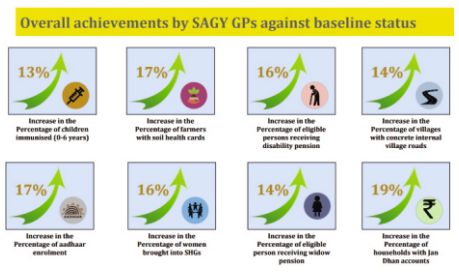

इस योजना के तहत एक साल में करीब 800 गांवों का कायाकल्प किए जाने का लक्ष्य था। सांसदों को विकास के लिए गांव चुनने की पूरी आजादी है हालांकि प्रधानमंत्री ने ये शर्त रखी है कि सांसद अपने गांव या अपने ससुराल को गोद नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से ही गांवों का विकास संभव नहीं है। मोदी ने इस योजना की तर्ज़ पर राज्यों से भी ऐसी स्कीम शुरु करने की अपील की है।

- प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सांसदों की होगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 तक कम से कम 2500 मॉडल गांव तैयार हो जाएंगे। मोदी ने इस योजना के तर्ज पर राज्यों से भी विधायकों के लिए ऐसी स्कीम शुरू करने के लिए कहा है।
- नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसदों को अपने गांव को छोड़कर कोई और गांव चुनने की पूरी आजादी होगी।

हम आपको बता दें कि किन गांवों को आदर्श बनाया जा रहा है और वहां क्या सुविधाएं मिलेंगी? मैदानी इलाकों में 3000–5000 की जनसंख्या वाले जबकि पहाड़ी इलाकों में 1000–3000 की जनसंख्या वाले गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। आदर्श ग्राम में अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, ई साक्षरता और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा होगी।

यही नहीं आदर्श गांव के सभी किसानों को सॉईल हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड और आधार कार्ड भी मिलेगा। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल भी बनाया जा सकता है। साथ ही आदर्श गांव अपना आर्थिक एजेंडा भी तय करेंगे।

सांसदों ने भी प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना की जमकर तारीफ की है। सांसदों के मुताबिक नई योजना से हर सांसद को प्रेरणा मिलेगी और गांवों का विकास होगा।

सांसद आदर्श योजना में गोद लिए गांव का विवरण :

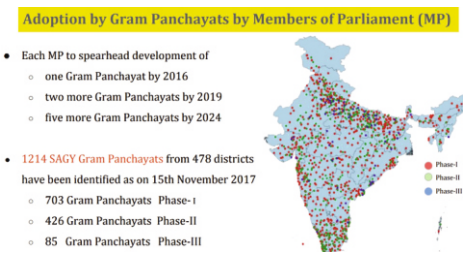

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयापुर गाँव को दत्तक ग्रहण किया है।

सोनिया गांधी ने राय बरेली

राहुल गांधी ने अमेठी

वी०के० सिंह ने मीरपुर हिन्दू

सचिन तेंदुलकर ने पट्टुर्म्रजू वारी कंदीग्रा

ग्राम पंचायत थड़ी की प्रधान आशा कश्यप क्या कहती है

शिमला ज़िले की ग्राम पंचायत थड़ी को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया और पूर्व राज्य सभा सांसद बिमला कश्यप ने शोघी की ग्राम पंचायत थड़ी को गोद लिया तथा लगभग एक करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए गए। पंचायत में जिन विकास कार्यों को करवाया गया है उसका विवरण

- मिनी स्टेडियम
- आंगनबाड़ी केन्द्र
- पॉली हाउस
- पुलों का निर्माण
- सोलर लाईटस्
- स्वयं सहायता समूहों का निर्माण
- शमशानघाट का निर्माण
- सड़कों का निर्माण आदि

प्रधान आशा कश्यप इस योजना की तारीफ करते हुए कहती है कि सांसद से मिले धन से ग्राम पंचायत का नक्शा ही बदल गया है।

साइड इफेक्ट

प्रधान का कहना है कि सांसद के कार्यकाल समाप्त होने पर नये सांसद ने इसके लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई और जो काम होने है, उनके लिए धन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसमें न तो केन्द्र सरकार अब रुचि दिखा रही है और न ही राज्य सरकारें।

मैंने 15 अगस्त को कहा था कि 11 अक्टूबर, जयप्रकाश जी के जन्म दिन पर इसकी guidelines पेश करेंगे। कुछ मित्रों में मुझे उसी शाम को Email करके, कहा कि मैंने एक गांव Select किया है, ऐसा मुझे बताया था। और वे भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं है। भाजपा के सिवा MP ने भी, कॉग्रेस के MPs ने भी मुझे लिखकर के दिया है। तभी मुझे लगा था कि बात में दम है। राजनीति से परे होकर के सबको इसको गले लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम आजमा रहे हैं। मैं सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है और सबके मार्गदर्शन में यह कोई योजना Ultimate नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे। बहुत सुधार आएंगे, बहुत व्यवहारिक बातें आएंगी। लेकिन ये रुपए–पैसों वाली योजना नहीं है। यह योजना People & Driven है, People*s Participation से होने वाली है और सांसद मार्गदर्शन में होने वाली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र

सांसद आदर्श ग्राम योजना Saansad Adarsh Gram Yojana

		Summary Report of Gam Pancayats for Saanjhi (Phase I)				Summary Report of Gam Pancayats for Saanjhi (Phase II)				Summary Report of Gam Pancayats for Saanjhi (Phase III)			
S. No.	State	Members of Lok Sabha	LS Members identified Gram Panchayats	Members of Rajya Sabha	RS Members identified Gram Panchayats	Members of Lok Sabha	LS Members identified Gram Panchayats	Members of Rajya Sabha	RS Members identified Gram Panchayats	Members of Lok Sabha	LS Members identified Gram Panchayats	Members of Rajya Sabha	RS Members identified Gram Panchayats
	Total	543	500	253	203	549	358	242	130	547	214	242	53
1	Andaman and Nicobar Islands	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2	Andhra Pradesh	25	24	10	7	25	14	10	5	25	11	10	3
3	Arunachal Pradesh	2	2	1	1	2	2	1	0	2	2	1	0
4	Assam	14	14	7	7	14	9	7	1	14	4	7	0
5	Bihar	40	40	16	13	41	15	13	3	41	8	13	0
6	Chandigarh	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
7	Chhattisgarh	11	11	5	5	11	11	5	5	11	9	5	3
8	Dadra And Nagar Haveli	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
9	Daman And Diu	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
10	Delhi	7	6	3	2	7	3	3	0	7	2	3	0
11	Goa	2	2	1	1	12	2	1	0	2	0	1	0
12	Gujarat	26	26	11	11	26	20	11	7	26	5	11	3
13	Haryana	10	10	5	5	10	8	5	3	10	15	5	1
14	Himachal Pradesh	4	4	3	3	4	4	3	1	4	2	3	1
15	Jammu And Kashmir	6	6	6	4	6	3	4	1	5	0	4	0
16	Jharkhand	14	14	6	6	14	13	6	6	14	6	6	5
17	Karnataka	28	28	12	10	28	14	12	3	28	0	12	1
18	Kerala	20	20	11	11	20	19	9	8	20	13	9	4
19	Lakshadweep	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
20	Madhya Pradesh	29	29	11	8	29	13	12	7	29	7	12	4
21	Maharashtra	48	48	19	19	48	33	19	11	48	10	19	4
22	Manipur	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
23	Meghalaya	2	2	1	1	2	1	1	1	2	0	1	1
24	Mizoram	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
25	Nagaland	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
26	Nominated	0	0	12	8	2	1	12	5	2	1	12	3
27	Odisha	21	19	10	9	21	10	10	2	21	6	10	0
28	Puducherry	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
29	Punjab	13	13	7	7	13	6	7	2	13	2	7	2
30	Rajasthan	25	25	10	9	27	22	11	8	27	11	11	2
31	Sikkim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
32	Tamil Nadu	39	39	18	17	39	38	18	17	39	35	18	10
33	Telangana	17	16	8	6	17	10	7	5	17	7	7	1
34	Tripura	2	2	1	1	2	1	1	0	2	0	1	0
35	Uttar Pradesh	80	79	34	25	81	74	30	23	80	60	30	4
36	Uttarakhand	5	5	4	2	5	4	3	2	5	2	3	0
37	WestBengal	42	5	16	0	42	2	16	0	42	2	16	0
	Total	543	500	253	203	549	358	242	130	547	214	242	53

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

MISSION RIEV

Ruralising India- Empowering Villages

RURALIZING INDIA-EMPOWERING VILLAGE RIEV
कि दुनिया देखती रह जाए

सबका साथ ही है मिशन की सफलता क्योंकि

2019

January

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

February

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

March

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

April

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

June

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

July

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

August

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

September

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

October

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

November

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

December

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

आईआइआरडी अवकाश सूची

अवकाश	दिनांक	दिन
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	शनिवार
महा शिवरात्री	04 मार्च	सोमवार
होली	21 मार्च	वीरवार
हिमाचल दिवस	15 अप्रैल	सोमवार
इद–उल–फितर	05 जून	बुधवार
स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	वीरवार
जन्माष्टमी	23 अगस्त	शुक्रवार
महात्मा गांधी जयंती	02 अक्तूबर	बुधवार
दशहरा	08 अक्तूबर	मंगलवार
दिवाली	28 अक्तूबर	सोमवार
गुरु नानक जयंती	11 नवंबर	सोमवार
क्रिसमस–डे	25 दिसंबर	वीरवार

सार्वजनिक सरकारी अवकाश

पूर्ण राजत्व दिवस	25 जनवरी
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
गुरू रवि दास जंयती	19 फरवरी
महा शिवरात्री	04 मार्च
होली	21 मार्च
रामनवमी	13 अप्रैल
डा.बीआर अंबेदकर जयंती	14 अप्रैल
हिमाचल दिवस	15 अप्रैल
गुड फ्राइडे	19 अप्रैल
परशुराम जयंती	07 मई
बुद्ध पूर्णिमां	18 मई
इद-उल-फितर	5 जून
संत गुरू कबीर जयंती	17 जून
इद-उल-जुहा (बकरीद)	12 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त
जन्माष्टमी	24 अगस्त
मुहर्रम	10 सितंबर
महात्मा गांधी जयंती	2 अक्तूबर
दशहरा	03 अक्तूबर
महर्षि बाल्मिकी जयंती	13 अक्तूबर
दिवाली	27 अक्तूबर
गुरू नानक जंयती	12 नवंबर
क्रिसमस-डे	25 दिसंबर

वैकल्पिक अवकाश

नववर्ष दिवस	01 जनवरी
लोहड़ी	13 जनवरी
मकर संक्रांति	14 जनवरी
बसंत पंचमी	10 जनवरी
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	01 मार्च
बैसाखी	14 अप्रैल
महावीर जयंती	17 अप्रैल
ईस्टर-डे	21 अप्रैल
महा अष्टमी	06 अक्तूबर
गोवर्धन पूजा	28 अक्तूबर
गुरू तेगबहादुर शहीदी दिवस	24 नवंबर
क्रिसमस संध्या	24 दिसंबर

महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश

रक्षा बंधन	15 अगस्त
करवाचौथ	17 अक्तूबर
भाईदूज	29 अक्तूबर

INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT SHIMLA
Bye pass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla H.P. 171006 India, Ph.: +91-177-2640761 Fax: +91-177-2843528 Web: missionriev.in , web: iirdshimla.org